



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 413]
No. 413]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 16, 1985/भाद्र 25, 1907
NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 16, 1985/BHADRA 25, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 1985

सांख्यिकी 738(2) —केंद्रीय सरकार, बहुराज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1984 (1984 का 51) की धारा 109 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

बहुराज्य सहकारी सोसायटी नियम, 1985

अध्याय 1. प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बहुराज्य सहकारी सोसायटी (रजिस्ट्रिकरण, गवस्यता, निवेश और प्रवेश) विधियों का निपटारा, अर्थात् और पुनर्क्षण) नियम, 1985 है।

(2) ये 16 सितम्बर, 1985 को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा व्यवस्थित न हो—

(1) "अधिनियम" में बहुराज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1984 (1984 का 51) अभिप्रेत है।

(2) "परन्तु" में इन नियमों में संलग्न प्रत्येक अभिप्रेत है।

(3) "साधारण अधिवेशन" में साधारण निकाय, जिसके अस्तित्व द्वारा 29 में निर्दिष्ट प्रतिनिधि साधारण निकाय भी है, का अधिवेशन अभिप्रेत है।

(4) "भारा" में अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

(5) "अनुसूची" में इन नियमों में संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है।

(6) उन शब्दों और पदों के जो अधिनियम में परिभाषित और प्रयुक्त हैं किन्तु जो इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ है जो उनके अधिनियम में हैं।

अध्याय 2

रजिस्ट्रिकरण

3. रजिस्ट्रिकरण के लिए आवेदन: (1) धारा 6 की उपधारा (1) के अर्थात् बहुराज्य सहकारी सोसायटी के रजिस्ट्रिकरण के लिए आवेदन प्रारूप 1 में किया जाएगा और धारा 6 की उपधारा (2) और उपनियम (2) और (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए आवेदकों द्वारा हस्ताक्षरित होगा और उनके साथ निम्नलिखित संलग्न किए जाएंगे:—

(क) बहुराज्य सहकारी सोसायटी की प्रस्तावित उपविधियों की चार प्रतियाँ जो दो प्रत्येक व्यक्ति द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित होंगी जिसने रजिस्ट्रिकरण के लिए आवेदन पर हस्ताक्षर किए हैं,

(ख) ऐसे व्यक्तियों की एक सूची जिन्होंने शेरर पंजी में अभिदाय किया है, उनमें से प्रत्येक के द्वारा अभिदाय की गई रकम और उनके द्वारा संवत् प्रवेश फीस ;

(ग) बैंक या बैंकों से एक प्रमाणपत्र जिसमें प्रस्तावित बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के पक्ष में जमा अतिशेष का उल्लेख किया गया है ;

(घ) एक स्कीम जिसमें यह स्पष्ट करते हुए व्योरे दर्शाया कि बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का कार्यकरण किस प्रकार आर्थिक रूप से सुवृद्ध हो गा ;

(ग) संप्रवर्तकी के संकल्प की एक प्रमाणित प्रति जो एक ऐसे आवेदन का नाम और पता विनिर्दिष्ट करेगी जिसको केन्द्रीय रजिस्ट्रार रजिस्ट्रिकरण के पूर्व नियमों के अधीन पत्र व्यावहार भेजेगा और रजिस्ट्रिकरण दस्तावेज प्रेषित करेगा या मीचेगा।

(2) जहां रजिस्ट्रिकृत की जाने वाली किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का कोई सदस्य कोई बहुराज्य सहकारी सोसाइटी या कोई सहकारी सोसाइटी है वहां, यथास्थिति, ऐसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी या सहकारी सोसाइटी का अध्यक्ष या मुख्य कार्यपालक उस बोर्ड द्वारा संकल्प द्वारा रजिस्ट्रिकरण और उपविधियों के आवेदन पर उसकी ओर से हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत किया जायगा और ऐसे संकल्प की एक प्रति आवेदन के साथ संलग्न की जायगी।

(3) जहां रजिस्ट्रिकृत की जाने वाली किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का कोई सदस्य कोई सरकारी कंपनी, निगमित निकाय या सोसाइटी रजिस्ट्रिकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रिकृत कोई सोसाइटी है वहां ऐसा सदस्य अपनी ओर से रजिस्ट्रिकरण और उपविधियों के लिए आवेदन पर हस्ताक्षर करने के लिए किसी व्यक्ति को सम्यक रूप से प्राधिकृत करेगा और ऐसा प्राधिकार देने वाले ऐसे संकल्प की एक प्रति आवेदन के साथ संलग्न की जाएगी।

(4) आवेदन के साथ ऐसे एक या अधिक आवेदकों के नाम की उपदर्शित करने वाले संकल्प की एक प्रति जो प्रस्तावित उपविधियों में ऐसा परिवर्तन या परिवर्धन करने के लिए प्राधिकृत है जैसा केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा सुझाया जाए, प्रस्तुत की जाएगी।

(5) केन्द्रीय रजिस्ट्रार को आवेदन या तो रजिस्ट्रिकृत डाक द्वारा भेजा जाएगा या दस्ती परिवर्त किया जायगा।

4. रजिस्ट्रिकरण :—(1) नियम 3 के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर केन्द्रीय रजिस्ट्रार आवेदन की विनिर्दिष्टियों को प्ररूप 2 में बनाए रखे जाने वाले आवेदनों के रजिस्टर में प्रविष्ट करेगा, आवेदन को क्रम संख्या देगा और उसकी एक प्राप्ति की रसीद जारी करेगा।

(2) यदि केन्द्रीय रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाता है कि प्रस्तावित बहुराज्य सहकारी सोसाइटी ने अधिनियम और नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किया है तो वह सोसाइटी और उसकी उपविधियों को, रजिस्टर कर सकेगा।

(3) जहां केन्द्रीय रजिस्ट्रार किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी को रजिस्टर करता है वहां वह उक्त सोसाइटी को अपने द्वारा हस्ताक्षरित एक रजिस्ट्रिकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा जिस पर उक्त सोसाइटी की रजिस्ट्रिकरण संख्या और रजिस्ट्रिकरण की तारीख वाली उसकी प्राधिकारिक मुद्रा होगी। केन्द्रीय रजिस्ट्रार रजिस्ट्रिकरण प्रमाणपत्र के साथ-साथ अपने द्वारा यथा-अनुमोदित और रजिस्ट्रिकृत उपविधियों की एक प्रमाणित प्रति भी देगा जो उस समय प्रवृत्त उक्त सोसाइटी की रजिस्ट्रिकृत उपविधियां होंगी।

5. सोसाइटियों और उपविधियों आदि के रजिस्ट्रिकरण की श्रवधि का विस्तार :—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय रजिस्ट्रार की रिपोर्ट पर, निम्नलिखित

के रजिस्ट्रिकरण के लिए छह मास में श्रवधिक की अनिश्चित कालावधि प्रस्तुत कर सकेगी,—

(i) धारा 7 की उपधारा (3) के परन्तुक के अधीन बहुराज्य सहकारी सोसाइटी;

(ii) धारा 9 की उपधारा (2) के परन्तुक के अधीन बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की उपविधियों का संशोधन; और

(iii) धारा 18 की उपधारा (2) के परन्तुक के अधीन सहकारी सोसाइटी की अधिकारिता का विस्तार करने वाली उपविधियों का संशोधन।

6. रजिस्ट्रिकरण से इंकार किया जाना :—जहां केन्द्रीय सरकार धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की रजिस्टर करने से इंकार करता है वहां वह ऐसे इंकार के आवेदन को, उसके कारणों सहित, उक्त सोसाइटी के नियम 3 के उपनियम (i) के खंड (इ) के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति को सूचित करेगा।

7. उपविधियों की विषयवस्तु :—बहुराज्य सहकारी सोसाइटी; निम्नलिखित विषयों के संबंध में उपविधियां बना सकेगी—

(i) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी और उसकी शाखाओं के नाम और रजिस्ट्रिकृत पते;

(ii) प्रवर्तन का क्षेत्र;

(iii) वे उद्देश्य जिनके लिए बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की स्थापना की गई है और वह प्रयोजन जिनके लिए इस की विधियों का उपयोग किया जा सकेगा;

(iv) सदस्यता के प्रवेश और उसको वापस लेने के लिए निबंधन और अर्हताएं;

(v) सदस्यों, जिनके अंतर्गत अभिलिखित सदस्य भी हैं, के विशेषाधिकार, अधिकार, कर्तव्य और दायित्व;

परन्तु अभिलिखित सदस्य बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की श्रास्तिधियों या लाभों में किसी भी रूप में किसी प्रकार के शेरर के लिए हकदार नहीं होंगे और उन्हें मतदान का अधिकार नहीं होगा ;

(vi) सदस्यों द्वारा वेद किमी धन राशि के संदाय में व्यक्तिक्रम के परिणाम;

(vii) सदस्यों के प्रत्याह्वरण, उनके हटाए जाने या उनके निष्कासन के लिए प्रक्रिया;

(viii) वह रीति जिसमें और वह सीमा जिस तक सोसाइटी की निधियों जुटाई जा सकेंगी; अधिकतम शेरर पंजी जिसे कोई सदस्य धारण कर सकेगा और वह प्रयोजन जिनके लिए निधियों का उपयोग किया जा सकेगा;

(ix) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के निदेशकों और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति और उनके हटाए जाने का ढंग और बोर्ड के कर्तव्य और शक्तियां;

(x) साधारण निकाय और बोर्ड के वार्षिक और विशेष अधिवेशन के संयोजन और संचालन का ढंग, सूचनाएं जारी किया जाना और वह कामकाज जिसका उसमें संव्यहार किया जा सकेगा;

(xi) शुद्ध लाभों का व्ययन;

(xii) उपविधियां बनाते, उनमें परिवर्तन करने और उनको निराकृत करने की शक्ति;

(xiii) अध्यक्ष या गमापति की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य और बहुमत का समर्थन खो देने पर उसका हटाया जाना;

(xiv) धारा 45 में वर्णित शक्तियां और कर्तव्यों के अनिश्चित मुख्य कार्यपालक की शक्तियां और कर्तव्य;

- (xv) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की ओर से दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए और वाद और अन्य विधिक कार्यवाहियाँ संस्थित करने और उनका प्रतिपाद करने के लिए अधिकारी या अधिकारियों का प्राधिकरण;
- (xvi) निधियों की अभिरक्षा और उनके विनिधान का ढंग;
- (xvii) लेखाओं को रखे जाने का ढंग;
- (xviii) बोर्ड की सदस्य सदस्या;
- (xix) वह राशि जिसमें उपविधियों के भग का दावा पाये गए किसी समय पर शास्त्रि अधिकारोपित की जा सकेंगी;
- (xx) जहाँ आवश्यक हो वहाँ अनुत्तिम बोर्ड का गठन;
- (xxi) सूचना भेजने की रीति;
- (xxii) आरक्षित निधि का उपयोग या संरचना;
- (xxiii) वह प्रयोजन जिसके लिए बहुराज्य सहकारी सोसाइटी, के परिणामपत्र की दशा में प्रतिशेष, यदि कोई हो का उपयोग किया जा सकेगा;
- (xxiv) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के बोर्ड और उसके अन्य निकायों के लिए निर्वाचन का संचालन जिसके अंतर्गत विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या भी है और रिटनिंग आफिसरों की नियुक्ति;
- (xxv) सदस्यों के प्रत्याहारण अभावता और उनकी मृत्यु की दशा में अनुमति की जाने वाली प्रक्रिया;
- (xxvi) शर्तें यदि कोई हों, जिनके अधीन किसी सदस्य के शेयर या हिस्से का अंतरण अनुज्ञात किया जा सकेगा;
- (xxvii) ऐसे सदस्यों द्वारा जिनपर किए गए संशोधनों के विनियोजन का ढंग;
- (xxviii) अधिनियम या नियमों के उपबंधों के अधीन बनाए रखे जाने वाले विभिन्न निधियों का गठन और उनका अनुवर्धन;
- (xxix) प्रतिनिधि साधारण निकाय का गठन जो बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के प्रतिनिधियों या सदस्यों से मिलकर बनेंगे और साधारण निकाय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए ऐसे प्रतिनिधियों के निर्वाचन की पद्धति;
- (xxx) जैसे, कारबार के संचालन का ढंग; जैसे विनिर्माण, क्रय, स्टोक, ग्रहण और अन्य संबद्ध विषय;
- (xxxi) सहकारी बैंकों और बहुराज्य थ्रिफ्ट और प्रत्यक्ष सोसाइटियों की दशा में,—
- (क) प्रति सदस्य अनुशेष अधिकतम उधार;
- (ख) सदस्यों की उधारों पर व्याज की अधिकतम दर;
- (ग) शर्तें जिन पर सदस्यों को उधार मंजूर किए जा सकेंगे;
- (घ) उधारों और अधिमो की मंजूरी के लिए और समय बढ़ाए जाने की मंजूरी के लिए तथा ऐसे उधारों, अधिमो प्राप्त के प्रतिपदाय के लिए प्रक्रिया;
- (ङ) ये परिस्थितियाँ जिनमें उधार वापिस मांगा जा सकेगा।

8. उप-विधियों का संशोधन : (1) बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी की उप-विधियों का संशोधन सोसाइटी के साधारण अधिवेशन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत द्वारा पारित संकल्प से किया जा सकेगा।

(2) ऐसा कोई संकल्प तब तक विधिमानी नहीं होगा जब तक कि प्रस्तावित संशोधन की सूचना बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी के सदस्यों को उप-विधियों के अनुसार न दी गई हो।

(3) ऐसे प्रत्येक मामले में जिसमें बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी अपनी उप-विधियों का संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, आकलन निम्नलिखित के साथ केन्द्रीय रजिस्ट्रार को किया जाएगा :

- (क) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट संख्या की प्रति;
- (ख) उस साधारण अधिवेशन की, जिसमें संशोधन किए गए थे, तारीख उपर्युक्त करने वाले विनिर्देशों, साधारण अधिवेशन बुलाने के लिए कितने दिन की सूचना दी गई है, ऐसे अधिवेशन की तारीख को सदस्यों को कृत संख्या, भगपूर्ति का गठन करने वाले संख्या, अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों का संख्या, मतदान के अधिकार का प्रयोग करने वाले संख्या, संशोधन के लिए मतदान करने वाले संख्या;
- (ग) ऐसे संशोधनों को न्यायोचित ठहराने वाले कारणों सहित किए जाने के लिए प्रस्तावित संशोधन के साथ प्रवृत्त सुसंगत उप-विधियों की एक प्रति;
- (घ) उप-विधियों के पाठ की चार प्रतियाँ जैसी वे संशोधन के पश्चात् होंगी जिन पर बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी के बोर्ड द्वारा इस निमित्त सम्यक्तः प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए हों;
- (ङ) बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी के सदस्यों का दी गई सूचना और उप-विधियों का संशोधन करने के लिए प्रस्ताव की एक प्रति;
- (च) साधारण अधिवेशन का समापन करने वाले प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित यह प्रमाणपत्र कि उप-नियम (1) और उप-नियम (2) और उप-विधियों में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन किया गया है; और
- (छ) ऐसी अन्य विशिष्टियाँ जो केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा इस निमित्त अपेक्षित हों;

(4) ऐसा प्रत्येक आवेदन ऐसे साधारण अधिवेशन की, जिसमें ऐसा संशोधन पारित किया गया था, तारीख से साठ दिन के भीतर किया जाएगा।

(5) जहाँ केन्द्रीय रजिस्ट्रार किसी बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी की उप-विधियों के संशोधन को रजिस्ट्रार करने से इंकार कर देता है वहाँ वह उसके कारणों सहित इंकार किए जाने का आदेश पारित करेगा और उसे इंकार किए जाने के आदेश की तारीख से सात दिन के भीतर बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी के मुख्य कार्यपालक को रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजेगा।

(6) इस नियम में ऊपर उल्लिखित प्रक्रिया ऐसी सहकारी सोसाइटी की उप-विधियों के संशोधन को लागू होगी जो धारा 18 के उपबंधों के अनुसार स्वयं को बहु-राज्य सहकारी सोसाइटियों में संपरिवर्तित करने की इच्छुक हैं।

9. सोसाइटी द्वारा रजिस्ट्रार फाइल का अुरखण :—(1) प्रत्येक बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी अपने रजिस्ट्रीकरण पत्र पर एक रजिस्ट्रार फाइल रखेगी जिसमें निम्नलिखित होगा :

- (क) रजिस्ट्रार प्रमाणपत्र;
- (ख) रजिस्ट्रीकृत उप-विधियाँ;
- (ग) संशोधनों के रजिस्ट्रार प्रमाणपत्र के साथ उप-विधियों के सभी रजिस्ट्रीकृत संशोधन;
- (घ) अधिनियम और नियमों की एक प्रति;

(2) रजिस्ट्रार फाइल कार्य के घण्टों के दौरान सभी समयों पर केन्द्रीय रजिस्ट्रार या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी या बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी के किसी सदस्य के निरोक्षण के लिए खुली रखी जाएगी।

10. बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के नाम में परिवर्तन -- (1) बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी के नाम में धारा 11 के अधीन इस प्रकार परिवर्तन किया जा सकेगा कि वह किसी जति या धार्मिक संस्था का निर्दिष्ट न करे और वह बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के उद्देश्यों में अभिगत न हो।

(2) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के नाम में प्रत्येक परिवर्तन उसकी उप-विधियों के संशोधन द्वारा किया जाएगा।

(3) केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा नाम में परिवर्तन का अनुमोदन कर दिए जाने के पश्चात् बहुराज्य सहकारी सोसाइटी एल रजिस्ट्रार प्रमाण-पत्र को संशोधन के लिए केन्द्रीय रजिस्ट्रार को भेजेगा जो सम्यक् रूप से संशोधन के पश्चात् उसे बहुराज्य सहकारी सोसाइटी को वापस भेज देगा।

अध्याय 3 -- बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का सदस्य और उनके अधिकार और दायित्व

11. सदस्यता के प्रवेश के लिए अनुमतिपत्र : जगत्परीक्षा -- (1) कोई भी व्यक्ति बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के सदस्य के रूप में तब तक सम्मिलित नहीं किया जाएगा, अथवा कि --

- (क) उसने बहुराज्य सहकारी सोसाइटी द्वारा अधिकृत प्रश्न, यदि कोई हो, में या केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा सदस्यता के लिए विनिर्दिष्ट प्रश्न में यदि कोई है, लिखित रूप में आवेदन नहीं किया है;
- (ख) उसका आवेदन बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के बोर्ड द्वारा अनुमोदन नहीं किया गया है;
- (ग) उसने शेयरों की न्यूनतम संख्या नहीं खरीदी है और उसकी कीमत पूर्णतया या लगत, उतनी सोमा में जितनी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की उप-विधियों में अधिकृत की जाए, संदत्त नहीं की है;
- (घ) उसने अधिनियम, नियमों और उप-विधियों में अधिकृत मश्रा अन्य शर्तों का पालन नहीं किया है;
- (ङ) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी या किसी सहकारी सोसाइटी या राष्ट्रीय सहकारी सोसाइटी या सहकारी या किसी सरकार के स्वामित्व, प्रोत्त या उसके द्वारा नियंत्रण, धन किंवा अन्य निगम या किसी व्यक्तियों के नियंत्रण, तब वह निर्गम हो या नहीं की दशा में, सदस्यता के लिए आवेदन के साथ यह संकल्प संलग्न नहीं किया जाता जो उसे ऐसी सदस्यता के लिए आवेदन करने के लिए प्राधिकृत करता है।

(2) कोई व्यक्ति बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के सदस्य के रूप में सम्मिलित किए जाने के लिए पात्र नहीं होगा, यदि --

- (क) उसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है;
- (ख) यदि वह किसी न्याय न्यायालय द्वारा दीवानी या अनुमतिपत्र दीवानिया न्याय निर्णीत किया गया है;
- (ग) यदि वह किसी राजनैतिक प्रकृति के अपराध में भिन्न किसी अपराध के लिए या किसी ऐसे अपराध के लिए जिसमें नैतिक अधमता और खेडमत्त, अभिहित नहीं है, दण्डादिष्ट किया गया है और दण्डादेश की समाप्ति की तारीख में एक वर्ष की अवधि व्यतीत नहीं हुई है।

(3) इन नियमों या बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की उप-विधियों में किसी बात के होते हुए भी यदि कोई सदस्य उप-विधियों (2) में निर्दिष्ट किसी निरर्हताओं के अधीन हो जाता है या रहने से हटा हो गया है तो उसके बारे में यह नमूना जाएगा कि वह उस तारीख में, जब निरर्हता उपगत की गई थी, सोसाइटी का सदस्य नहीं रह गया है।

(4) कोई व्यक्ति किसी प्राथमिक स्तर की बहुराज्य सहकारी सोसाइटी या किसी बहुराज्य प्रथम सोसाइटी या किसी बहुराज्य तृतीय सहकारी तृतीय सहकारी के रूप में केन्द्रीय रजिस्ट्रार की संधारण या विशेष अनुज्ञा के बिना किसी अन्य बहुराज्य सहकारी सोसाइटी या, उमा, वर्ग का सहकारी सोसाइटी का सदस्य नहीं होगा और उमा कोई व्यक्ति एकीकृत ऐसा सहकारी सोसाइटी का सदस्य बन गया है तो या तो उसमें से एक या दोनों हा सोसाइटी या केन्द्रीय रजिस्ट्रार में उस उमा की लिखित उमा पर उसे सदस्यता से हटाने के लिए अवसर होगी।

(5) कोई बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अपने साधारण नियम के उमा के तारीख के पूर्व तीन दिन के भीतर सदस्यों को प्रवेश नहीं देगी।

12. भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ में व्यक्ति सदस्य : भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ लिमिटेड, नई दिल्ली के भूतपूर्व अध्यक्ष जिन्होंने अपने पद पर पूर्ण अवधि पूरी की है और सद्य में 15 से अधिक अन्य व्यक्ति जिनको सहकारीता के क्षेत्र में जान और प्रामुख है, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ लिमिटेड, नई दिल्ली, के सदस्यों के रूप में सम्मिलित किया जा सकेगा;

परन्तु यह तब जब कि सदस्यों के रूप में सम्मिलित किए गए भूतपूर्व अध्यक्ष और अन्य व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ लिमिटेड के किसी निर्वाचन में मतदान करने का निर्वाचन लड़ने के लिए पात्र नहीं होंगे।

13. शेयरों का प्रतिदाय : किसी सहकारी वर्ष में किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की शेयर पूंजी का कुल प्रतिदाय टीका पूर्ववर्ती सहकारी वर्ष के अंतिम दिन की बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की समाप्त शेयर पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

14. वारिस का नाम निर्देशन : (1) धारा 27 की उप-धारा (1) के अधीन उसके शेयर या हित के अंतरण के प्रयोजनों के लिए किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का कोई सदस्य किसी ऐसे व्यक्ति को नामनिर्देशित कर सकेगा जिसको उसकी मृत्यु की दशा में, उसका शेयर या हित अंतरित किया जाएगा। ऐसा सदस्य, समय समय पर ऐसे नामनिर्देशन को प्रतिमहत्त कर सकेगा या उसमें फेरकार कर सकेगा।

(2) किसी सदस्य द्वारा किया गया नामनिर्देशन तब तक विधिमन्य नहीं होगा और सदस्य की मृत्यु की दशा में तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि :

(क) वह लिखित रूप में न किया जाए और उस पर अनुप्रमाणित करने वाले दो साक्षियों की उपस्थिति में सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर न कर किए गए हो;

(ख) वह इस प्रयोजन के लिए बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की विधियों में अभिलिखित न किया गया हो।

15. सदस्य के शेयर या हित के मूल्य का अभिनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया : जहां किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का कोई सदस्य उसका सदस्य नहीं रह जाता है वहां, यथास्थिति, उसको या उसके नामनिर्देशनी, या वारिस या विधिक प्रतिनिधि को संदत्त की जाने वाली बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की पूंजी में उसके शेयर या हित के मूल्य को जताने वाली धनराशि, निम्नलिखित रीति में अभिनिश्चित की जाएगी, अर्थात् --

(i) असीमित दायित्व वाली बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की दशा में वह वास्तविक रकम जो ऐसे शेयर या हित की वास्तव बहुराज्य सहकारी सोसाइटी द्वारा अधिप्राप्त की गई है;

(ii) सीमित दायित्व वाली बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की दशा में, वह रकम जो सदस्यता की समाप्ति के पूर्व पिछले संपरीक्षित

तुलनपत्र में यथारहित ऐसी सोसाइटी की वित्तीय स्थिति पर आश्रित मूल्यांकन द्वारा निकाली गई है :

परन्तु इस प्रकार अभिविधित रकम ऐसे हित या शेषर की वास्तव बहुराज्य सहकारी सोसाइटी द्वारा अभिप्राय की गई वास्तविक रकम से अधिक नहीं होगी ।

16. शेयरों के धारण परनिर्वन्धन :—धारा 19 की उपधारा (1) के खण्ड (क) और (ज) में निर्दिष्ट कोई सदस्य बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की शेयर पूंजी के पांचवें भाग से अधिक धारण नहीं करेगा या दसहजार रुपए से अधिक के बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के शेयर, इन दोनों में से जो भी कम हो, नहीं लेगा या उन पर दावा नहीं करेगा ।

17. शेयर का आडमान न किया जाता :—बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के शेयरों को उस सोसाइटी या किसी अन्य बहुराज्य सहकारी सोसाइटी को उधार के लिए प्रतिभूति के रूप में सदस्यों द्वारा आडमानित नहीं किया जाएगा ।

18. साधारण अधिवेशन के अवसर पर सदस्यों के प्रवेश और शेयरों के अन्तरण पर प्रतिबंध :—(1) कोई बहुराज्य सहकारी सोसाइटी साधारण निकाय के अधिवेशन के लिए नियत तारीख के पूर्व तीस दिन के भीतर सदस्यों को सम्मिलित नहीं करेगा या शेयरों का अन्तरण अनुमोदित नहीं करेगा ।

(2) इस नियम के उल्लंघन से सदस्य के रूप में सम्मिलित किए गए किसी व्यक्ति को और ऐसे किसी व्यक्ति को जिसके पक्ष में शेयरों का अन्तरण अनुमोदित किया गया है, उक्त साधारण अधिवेशन में मतदान का अधिकार नहीं होगा ।

19. व्यक्तिकी सदस्य की निर्दिष्टता :—बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का कोई सदस्य या व्यक्तिकी सदस्य सोसाइटी का कोई प्रतिनिधि ऐसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के बोर्ड में किसी पद पर निर्वाचन लाने का या उसके सदस्य के रूप में बने रहने का पात्र नहीं होगा यदि वह या वह सोसाइटी जिसका वह प्रतिनिधि है ऐसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी को देय वार्षिक अभिदान या अन्य धनराशि के संदाय में व्यक्तिकम करता है । कोई सदस्य या व्यक्तिकी सदस्य सोसाइटी का कोई प्रतिनिधि, यदि किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी में कोई पद धारण किए हुए है, तो उसका उस तारीख से जिसको वह या वह सोसाइटी जिसका वह प्रतिनिधि है, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की उपविधियों के अनुसार या बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के निदेशक बोर्ड द्वारा अवधारण के अनुसार व्यक्तिकी हो जाना है, ऐसा पद धारण करने का अधिकार समाप्त हो जाएगा ।

अध्याय 4—बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों के निवेश और प्रबन्ध :

20. वार्षिक साधारण अधिवेशन :—प्रत्येक बहुराज्य सहकारी सोसाइटी सहकारी वर्ष की समाप्ति के छह मास के भीतर अपने सदस्यों (धारा 30 में निर्दिष्ट) का वार्षिक साधारण अधिवेशन आयोजित करेगी ।

21. छोटे साधारण निकाय का गठन :—(1) धारा 29 की उपधारा (3) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी, जिसकी सदस्यता एक हजार से अधिक है, अपनी उपविधियों में एक छोटे साधारण निकाय के गठन का उपबंध कर सकेगी । इस प्रकार गठित किया गया छोटा साधारण निकाय ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की उपविधियों में विनिर्दिष्ट की जाएंगी ।

(2) ऐसी सोसाइटी की उपविधियों में किसी प्रतिनिधि साधारण निकाय के गठन का सिद्धांत या आधार और उसकी प्रक्रिया विनिर्दिष्ट की जा सकेगी ।

22. अंतिम बोर्ड और प्रथम निर्वाचन के लिए साधारण अधिवेशन—
(1) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदकों द्वारा

चयन किया गया निदेशक बोर्ड तब तक पद धारण करेगा जब तक कि निदेशक बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के प्रथम साधारण अधिवेशन में निर्वाचित नहीं हो जाते हैं ।

(2) इस प्रयोजन के लिए प्रथम साधारण अधिवेशन बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के छह मास के भीतर आयोजित किया जाएगा ।

23. साधारण अधिवेशन के लिए सूचना :—(1) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का वार्षिक साधारण अधिवेशन चौदह दिन से अग्र्यून की लिखित सूचना देकर बुलाया जा सकेगा ।

(2) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का विशेष साधारण अधिवेशन सात दिन से अग्र्यून की लिखित सूचना देकर बुलाया जा सकेगा ।

(3) जब कोई साधारण अधिवेशन धारा 30 की उपधारा (1) के द्वितीय परन्तुक के अर्थान् केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा बुलाया जाता है तो वह,—

(1) ऐसे अधिवेशन की सूचना की अवधि ज्ञात सात दिन से कम नहीं होगी,

(2) ऐसे अधिवेशन का समय और स्थान; और

(3) ऐसे अधिवेशन में विचार-विमर्श किए जाने वाले विषयों को, अवधारित कर सकेगा ।

केन्द्रीय रजिस्ट्रार या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति ऐसे अधिवेशनों की अध्यक्षता कर सकेगा ।

(4) साधारण अधिवेशन की सूचना के साथ पूर्ववर्ती वर्ष से सबधित लेखापरीक्षित तुलनपत्र, लाभ और हानि लेखा की एक प्रति, उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट सहित मंजूर की जाएगी और उसके साथ बोर्ड की रिपोर्ट होगी ।

24. साधारण अधिवेशन में गणपूर्ति—(1) जब तक कि उपविधियों में अन्यथा उपबंधित न किया जाए, साधारण अधिवेशन के लिए गणपूर्ति बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के सदस्यों की कुल संख्या का पांचवां भाग होगी ।

(2) किसी साधारण अधिवेशन में किसी भी कामकाज का संव्यवहार तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि अधिवेशन का कामकाज प्रारम्भ होने के समय अधिवेशन में गणपूर्ति पूरी नहीं है ।

(3) यदि अधिवेशन के पहले नियत समय से आधा घंटे के भीतर गणपूर्ति उपस्थित नहीं है तो अधिवेशन स्थगित हो जाएगा ।

परन्तु ऐसा अधिवेशन जो सदस्यों की अध्यक्षता पर बुलाया गया है, स्थगित नहीं होगा अगितु विघटित हो जाएगा ।

(4) यदि अधिवेशन के दौरान किसी समय सदस्यों की पर्याप्त संख्या गणपूर्ति को पूरा करने के लिए उपस्थित नहीं है तो अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला अध्यक्ष या सदस्य स्वयं या उसतथ्य की ओर उसका ध्यान आकर्षित किए जाने पर, वह अधिवेशन स्थगित कर देगा और वह कामकाज जो ऐसे अधिवेशन, यदि कोई है, में संव्यवहारित किया जाना शेष रह जाना है, स्थगित अधिवेशन में प्राधिकारीति में निरूपाया जाएगा ।

(5) जहां कोई अधिवेशन उपनियम (3) या उपनियम (4) के अधीन स्थगित कर दिया जाता है, वहां स्थगित अधिवेशन या तो उसी दिन या ऐसे दिन, समय और स्थान पर जो ऐसे अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले अध्यक्ष या सदस्य द्वारा विनिश्चित किया जाए, आयोजित किया जाएगा ।

(6) किसी स्थगित अधिवेशन में स्थगित अधिवेशन की कार्यसूची में दिए गए कामकाज से भिन्न किसी कामकाज का संव्यवहार नहीं किया जाएगा ।

(7) स्वयं साधारण अधिवेशन के संबंध में कोई गणना आवश्यक नहीं होगी।

25. साधारण अधिवेशन में मतदान—(1) ऐसे सभी संकल्प जिन्हें साधारण अधिवेशन में मतदान के लिए रखा जाता है, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किये जाएंगे, जब तक अधिनियम, इन नियमों या बहुराज्य सहाकारी सोसाइटी की उपविधियों के अधीन अन्यथा अपेक्षित न हो। मतदान हाथ उठाकर किया जाएगा जब तक कि मतदान की मांग अधिवेशन में उपस्थित कम से कम दस सदस्यों द्वारा नहीं की जाती है। यदि किसी मतदान की मांग नहीं की जाती है तो ऐसे अधिवेशन के अध्यक्ष सभापति द्वारा यज्ञोपवीता कि संकल्प पारित कर दिया गया है या पारित नहीं हुआ है और कार्यवाहियों के कार्यभार में उस प्राणय की प्रविष्टि इस तथ्य का विनिश्चयात्मक सबूत होगी कि ऐसा संकल्प पारित किया गया है या पारित नहीं हुआ है।

(2) यदि किसी मतदान की मांग की जाती है तो मतदान मतपत्रों द्वारा होगा जैसा अधिवेशन के अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जाए जब तक कि इस निमित्त उपविधियों में अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो और मतदान का परिणाम ऐसे संकल्प के बारे में जिस पर मतदान की मांग की गई है, साधारण अधिवेशन का विनिश्चय माना जाएगा।

(3) जब कोई मतदान होता है तो किसी संकल्प के पक्ष या विपक्ष में मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या कार्यवाहियों के कार्यभार में अधिविहित की जाएगी।

(4) हाथ उठाकर या मतदान के आधार पर मतों के बराबर होने की वशा में ऐसे अधिवेशन के अध्यक्ष का जिसमें हाथ उठाए जाते हैं या मतदान होता है, द्वितीय या निर्णायक मत होगा।

26. साधारण अधिवेशन के कार्यभार—(1) साधारण अधिवेशन की कार्यवाहियों के कार्यभार इन प्रयोजनों के लिए रखी गई एक कार्यभार पुस्तक में प्रविष्टि किए जाएंगे और उन पर अधिवेशन के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस प्रकार हस्ताक्षरित कार्यभार, उस अधिवेशन की सही कार्यवाहियों का माध्यम होगी।

27. निर्वाचन के संचालन के लिए प्रक्रिया—(1) इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी और धारा 35 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार की शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अधिनियम की दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय सहाकारी सोसाइटी और ऐसी अन्य बहुराज्य सहाकारी सोसाइटी या किसी वर्ग की बहुराज्य सहाकारी सोसाइटी के जो केन्द्रीय सरकार, किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा, अधिसूचित करे, निदेशक बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन ऐसे रिटनिंग आफिसर या आफिसरों द्वारा किया जाएगा जो केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा इस निमित्त नियुक्त किए जाएंगे। ऐसी सोसाइटियों में निर्वाचन का संचालन अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से किया जाएगा।

(2) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी जहां निर्वाचन का संचालन करने के लिए किसी रिटनिंग आफिसर की नियुक्ति करने के लिए कोई अपेक्षा किसी बहुराज्य सहाकारी सोसाइटी में मतदान करने के लिए पात्र सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम पांचवें भाग से निर्वाचन की तारीख से साठ दिन पहले प्राप्त हो जाती है तो केन्द्रीय रजिस्ट्रार अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में निर्वाचन का संचालन करने के लिए एक निर्वाचक अधिकारी को नियुक्त करेगा।

28. पदधारियों का निर्वाचन—बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन हो जाने के पश्चात् नियम 27 के उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट रिटनिंग आफिसर या यथास्थिति साधारण अधिवेशन में अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति, सूचना की अवधि विनिर्दिष्ट करने वाली बहुराज्य सहाकारी सोसाइटी की उपविधियों में किसी बात के होते हुए भी, सोसाइटी के सभापति/अध्यक्ष, उपसभापति/उपाध्यक्ष या अन्य निर्वाचित पदधारियों के, चाहे वे किसी भी नाम से जाने जाते हों, निर्वाचन के प्रयोजन के लिये बोर्ड

नवनिर्वाचित सदस्यों का अधिवेशन संयोजित करेगा। बोर्ड के ऐसे अधिवेशन का संचालन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक उपविधियों के अनुसार नवगठित बोर्ड के बहुसंख्यक सदस्य उपस्थित न हों।

29. संचालित निर्वाचनों के अधिलेख की अभिरक्षा—निर्वाचन के परिणाम की घोषणा के पश्चात् यथास्थिति रिटनिंग आफिसर (नियम 27 के उपनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट) या अधिवेशन का अध्यक्ष, निदेशक बोर्ड के सदस्यों और पदधारियों के निर्वाचन से संबंधित मतपत्रों और अधिलेखों, यदि कोई हों, को सीलबंद लिफाफों में बहुराज्य सहाकारी सोसाइटी के मुख्य कार्यपालक को सौंप देगा। वे सोसाइटी के मुख्य कार्यपालक द्वारा निर्वाचन की तारीख से छह मास की अवधि तक या ऐसे समय तक जब तक निर्वाचन, यदि कोई है, की बाबत उसके किसी विवाद या अपील का निपटारा नहीं कर दिया जाता है, इन दोनों में से जो भी बाद में हो, परिरक्षित किए जाएंगे और तत्पश्चात् नष्ट कर दिए जाएंगे।

30. अध्यक्ष और सभापति की मानदेय के संदाय के लिए निबंधन और शर्तें—बहु राज्य सहाकारी सोसाइटी अपनी उप विधियों में निदेशक बोर्ड के निर्वाचित अध्यक्ष या सभापति को, उसके द्वारा की गई विनिर्दिष्ट सेवाओं की बाबत, ऐसे मापमान पर जो ऐसी किसी सोसाइटी की उपविधियों में अधिकृत किया जाए, लाभों में से, मानदेय के संदाय का का उपबंध कर सकेगी किन्तु कितनी भी वशा में वह नीचे निर्दिष्ट सीमा तथा निबंधनों और शर्तों के उल्लंघन में नहीं होगा।

(क) यह कि सोसाइटी की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ है;

(ख) यह कि उसके व्यय पुनः उपगत करने के लिए वह केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार से प्राप्त अनुदानों या सहायिकी पर निर्भर नहीं करती है; और

(ग) यह कि संघर्ष किए जाने वाला मानदेय, चाहे वह समेकित रकम के रूप में हो या मुख्यालय में बिराम के वित्तों की बाबत दैनिक भत्ते के रूप में हो, बोर्ड के अधिवेशनों की की बाबत, जब और जैसे ऐसे अधिवेशन आयोजित किए जाते हैं, बैठक फीस के अनतिरिक्त पच्चीस हजार रुपये प्रतिवर्ष तक सीमित होगा।

31. बोर्ड में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के नामनिर्देशित—जहां केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार ने किसी बहुराज्य सहाकारी सोसाइटी की शेर पूंजी में अभिदाय किया है या ऐसी सोसाइटी द्वारा जारी किए गए डिबेंचरों पर मूल के प्रसिद्धा और व्याज के संदाय की प्रत्याभूति दी है या ऐसी सोसाइटी को उधारों और अग्रिमों पर मूल के प्रसिद्धा और व्याज के संदाय की प्रत्याभूति दी है या ऐसी सोसाइटी को अनुदान या सहायिकी का उपबंध किया है, बहाल, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को बोर्ड में उसके कुल सदस्यों की संख्या के तीन या एक तिहाई से इन दोनों में से जो भी कम हो, से अधिक व्यक्तियों की संख्या को, नामनिर्देशित करने का अधिकार होगा।

(2) इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी बहु राज्य सहाकारी सोसाइटी की उपविधियों में उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक व्यक्तियों के केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशन का उपबंध किया जा सकेगा।

32. बोर्ड द्वारा किए जाने वाले अतिरिक्त व्ययों और कार्य—बोर्ड नीचे उल्लिखित ऐसे कोई प्रयुपाय या कोई कार्य कर सकेगा, जो अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन उसके कृत्यों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन हों—

(1) साधारण निकाय के समक्ष वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षा रिपोर्ट का प्रस्तुत किया जाना;

- (ii) साधारण निकाय के समक्ष साधनों के विस्तारण की सिफारिश करना;
- (iii) प्रत्याहरण, अन्तर्गण, सेवानिवृत्ति, श्रेयों के प्रतिदाय या समपहरण से संबंधित विषयों पर विनिश्चय करना;
- (4) ऐसे मूल्य की, जो उपविधियों में विनिर्दिष्ट की जाएं, जंगम सम्पत्ति का क्रय, विक्रय या अन्यथा उसका अर्जन या व्ययन;
- 5) सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत अवधारित करने के लिए मापदण्ड विहित करना;
- 6) अन्य सहकारी सोसाइटियों और अन्यो के साथ सहयोग के निबंधन और शर्तों का अवधारण;
- 7) किसी मूल्य की संविदाओं को मंजूरी देना जब तक कि किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की उपविधियों में अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया हो;
- 8) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के कारबार के लिए न्यायी या न्यासियों, अटर्नी या प्रभटनियों, अधिकर्ता या अभिकर्तियों की नियुक्ति;
- (ix) बोर्ड के सदस्यों से त्यागपत्र का स्वीकार किया जाना या अस्वीकार किया जाना।

33. बोर्ड के अधिवेशन.—(i) बोर्ड का अधिवेशन प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार आवश्यक होगा, परन्तु बोर्ड के अधिवेशनों की कुल संख्या साधारणतः एक वर्ष में छह से अधिक नहीं होगी।

परन्तु यह और कि यह उपबंध बहुराज्य छिद्र और प्रत्यय सोसाइटियों को लागू नहीं होगा।

(ii) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के बोर्ड का अधिवेशन साधारणतः ऐसी सोसाइटी के रजिस्ट्रिकृत कार्यालय में आयोजित किया जायगा।

34. बोर्ड की समितियाँ—(1) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का बोर्ड कार्यपालक समिति और ऐसी अन्य समितियाँ या उपसमितियाँ गठित कर सकेगा जो आवश्यक समझी जायगी।

(ii) कार्यपालक समिति के अतिरिक्त धारा 4-6 की उपधारा (1) में निश्चित अन्य समितियों और उप समितियों की संख्या दो से अधिक नहीं होगी;

परन्तु बोर्ड केन्द्रीय रजिस्ट्रार के अनुमोदन से दो से अधिक समितियों का गठन कर सकेगा।

35. राष्ट्रीय सहकारी सोसाइटी चयन समिति का गठन (1) केन्द्रीय सरकार एक ऐसे निकाय का गठन करेगी जो राष्ट्रीय सहकारी सोसाइटी चयन समिति (जिसे इसमें इसके आगे चयन समिति कहा गया है) के नाम से जाना जाएगा और जो निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगा :

- (i) सचिव, भारत सरकार, कृषि और सहकारिता विभाग
- (ii) उपर सचिव, भारत सरकार, कृषि और सहकारिता विभाग, जो सहकारिता का भारसाधक —सदस्य
- (iii) दो राष्ट्रीय सहकारी सोसाइटियों के अध्यक्ष जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा —सदस्य
- (iv) प्रबंध में एक विशेषज्ञ जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायगा —सदस्य
- (v) प्रबंध निवेशक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम —सदस्य
- (vi) सहकारी सोसाइटियों का केन्द्रीय रजिस्ट्रार —सदस्य सचिव

(2) चयन समिति राष्ट्रीय सहकारी सोसाइटियों में मुख्य कार्यपालक के पद और अन्य प्रबंधकीय पदों पर नियुक्ति के लिये पात्र व्यक्तियों की

इसमें इसके आगे दी गई रीति में एक सूची तैयार करेगी जिनका अधिकतम वर्तमान चार हजार रुपए प्रति माह से अधिक है।

(3) केन्द्रीय रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय सहकारी सोसाइटी से प्राप्त अध्यक्षा पर, ऐसे पद या पदों पर जिनके लिये अध्यक्षा प्राप्त हुई है नियुक्तियों के लिये सूची तैयार करने के प्रयोजन के लिए चयन समिति का अधिवेशन संयोजित करेगा।

(4) चयन समिति,—

(क) उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट पदों के लिए विज्ञापन निकालने, पत्र परिचालित करने या उनके लिये अन्यथा नाम मंगाने के लिये समुचित कार्रवाईयाँ करेगी;—

(ख) उक्त पदों पर नियुक्ति के लिये प्राप्त नामों की जांच करेगी और यदि आवश्यक हो, तो साक्षात्कार के पश्चात् योग्यताक्रम में ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी और उसे संबद्ध राष्ट्रीय सहकारी सोसाइटी को आगे भेज जाने के लिये, केन्द्रीय सरकार को भेजेगी;

परन्तु विद्यमान मुख्य कार्यपालक या ऐसे व्यक्तियों की दशा में जो इन नियमों के प्रवर्तन की तारीख को राष्ट्रीय सहकारी सोसाइटी में अन्य प्रबंधकीय पदों पर नियोजित हैं और जो सोसाइटी के नियमित नियोजन में हैं, चयन समिति को ऐसा कोई निर्देश आवश्यक नहीं होगा;

परन्तु यह और कि मुख्य कार्यपालक या अन्य प्रबंधकीय पदों पर नियोजित व्यक्तियों की दशा में जो इन नियमों के प्रवर्तन की तारीख को राष्ट्रीय सहकारी सोसाइटी में प्रतिनियुक्ति पर है, ऐसे मुख्य कार्यपालक या व्यक्तियों की प्रतिनियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर चयन समिति को निर्देश करना आवश्यक होगा।

(5) राष्ट्रीय सहकारी सोसाइटी चयन समिति द्वारा सिफारिश किए गए व्यक्तियों की सूची में से उपनियम (2) में वर्णित मुख्य कार्यपालक के पद और अन्य प्रबंधकीय पदों पर व्यक्तियों को नियुक्त करेगी।

(6) चयन समिति व्यक्तियों के चयन के समय पदों या पदों के प्रवर्ग की अपेक्षाओं के अनुसार, जिनके लिये व्यक्तियों की सूची तैयार की जानी है, दो विशेषज्ञों को सहयोजित कर सकेगी।

अध्याय— 5

विवादों का निपटारा

36. केन्द्रीय रजिस्ट्रार के समक्ष कार्यवाहियों में प्रक्रिया

(1) धारा 74 के अधीन किसी विवाद का केन्द्रीय रजिस्ट्रार को निवेदन लिखित रूप में होगा। ऐसे प्रत्येक निर्देश के साथ एक हजार रुपये में अतः केन्द्रीय दावों के लिये सम रुपये की फीस और अन्य सभी मामलों में पचास रुपये की फीस संलग्न की जाएगी।

(2) उपनियम (1) के अधीन निर्देश की प्राप्ति पर केन्द्रीय रजिस्ट्रार विवाद का या तो स्वयं विनिश्चय कर सकेगा या उसे निपटारा जाने के लिये किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को निर्देशित कर सकेगा जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 76 के अधीन केन्द्रीय रजिस्ट्रार की शक्तियों से विनिर्दिष्ट किया गया है।

(3) केन्द्रीय रजिस्ट्रार या विवाद का विनिश्चय करने वाला कोई अन्य व्यक्ति ऐसे पक्षकारों और माधियों के साक्ष्य का एक संक्षिप्त टिप्पण अभिलिखित करेगा जो उसके सम उपस्थित हुए हैं और इस प्रकार अभिलिखित साक्ष्य के आधार पर और पक्षकारों द्वारा पेश की गई किसी दस्तावेजों साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात्, केन्द्रीय रजिस्ट्रार या विवाद का विनिश्चय करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, न्याय, साम्प्रदाय और गुप्त अन्तर्करण के अनुसार विनिश्चय किया जाएगा। विनिश्चय लिखित रूप में होगा।

उपस्थित होने के लिए सम्बन्ध रूप से शतवत् या किम्. पक्षकार को, अनुपस्थिति में विवाद का विनिश्चय—कमर्श या रूप से किया जा सकेगा। पक्षधारी विनिश्चय, अनुपस्थित होने के पर्याप्त हेतु द्योतित कर दिए जाने पर केन्द्रीय रजिस्ट्रार या विवाद का विनिश्चय करने वाले अन्य व्यक्ति द्वारा अपनाया किया जा सकेगा और विवाद के बारे में यह आदेश किया जा सकेगा कि वह विवादों के रजिस्ट्रार में पुनः निषेध लागू और उसका निपटारा जाय ;

परन्तु पक्षधारी विनिश्चय अपारत करने के लिए कोई आवेदन तब तक नहीं होगा जब तक कि वह ऐसे विनिश्चय का की तारीख से तीन दिन के भीतर नहीं किया जाता है और ऐसे पक्षकार पर जिसकी अनुमति के कारण ऐसा विनिश्चय किया गया था, सूचना की सम्यक् तारीख नहीं की जाती है या अन्य मामलों में ऐसे विनिश्चय की जानकारी होने के तारीख से नौ दिनों के भीतर ऐसा आवेदन नहीं किया जा सकता है।

(4) विनिश्चय पक्षकारों की निम्नलिखित द्वारा संसूचित किया जाएगा—

(i) विनिश्चय को, उद्घोषणा, या

(ii) किम ऐसे पक्षकार को जो उस तारख की जब विनिश्चय दिया गया था, अनुपस्थित हो, रजिस्ट्रार डाक द्वारा।

(5) केन्द्रिय रजिस्ट्रार या विवाद का विनिश्चय करने वाले व्यक्ति को विवाद के पक्षकार के लिए कोई संरक्षक नियुक्त करने या हटाने का शक्ति होगा यदि ऐसा कोई पक्षकार अप्राप्तस्थ है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो विकृतचित्त या मानसिक दोषरूप में ग्रस्त है और जो अपने हितों का रक्षा करने में असमर्थ है।

(6) विनिश्चय को सम्यक् रूप से प्रमाणित प्रति, आवेदन किए जाने पर केन्द्रीय रजिस्ट्रार या विवाद का विनिश्चय करने वाले व्यक्ति द्वारा एक रूप प्रवि पृष्ठ के दर से तबल प्रसार के संदेश पर विवाद के पक्षकारों को दे जाएगा।

अध्याय-6

अपल और पुनरक्षण

37. केन्द्रिय रजिस्ट्रार के आदेश के विरुद्ध अपल प्रवर्तित करने के धारा 90 का उपधारा (2) के खण्ड (क) के प्रयोजन के लिए किम्. विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध अपल, यदि विनिश्चय या आदेश—

(क) अधिनियम का धारा 4 का उपधारा (1) के अधिनियमित केन्द्रिय रजिस्ट्रार द्वारा किया जाता है, तो सचिव कृषि और सहकारिता विभाग को;

(ख) केन्द्रिय सरकार के किम्. अधिकार, या रजिस्ट्रार का पंक्ति के राज्य सरकार के किम्. अधिकार, द्वारा जिसका केन्द्रिय रजिस्ट्रार को शक्तियाँ, अधिनियम का धारा 4 का उपधारा (2) के अधिनियमित क गई है, किया जाता है, तो अपर सचिव, भारत सरकार, कृषि और सहकारिता विभाग को;

(ग) राज्य सरकार के किम्. अन्य अधिकार, द्वारा जिसको केन्द्रिय रजिस्ट्रार को शक्तियाँ, अधिनियम का धारा 1 का उपधारा (2) के अधिनियमित क गई है, किया जाता है तो मुख्य निदेशक (सहकारिता) कृषि और सहकारिता मंत्रालय को, दिया जाएगा।

38. पुनरक्षण के लिए अपल और आवेदन का वास्तव प्रक्रिया

(1) धारा 90 का उपधारा (2) के अधिनियमित, अपल या धारा 92 के अधिनियमित पुनरक्षण के लिए आवेदन, अपल या पुनरक्षण प्राधिकार, को तो व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया जाएगा या रजिस्ट्रार डाक द्वारा भेजा जाएगा।

(2) पुनरक्षण के लिए अपल, या आवेदन, अपल के रूप में होगा और उसके साथ एक प्रार्थना के लिए अपल के विरुद्ध अपल का गई है या जिसको पुनरक्षण किया जाता है, तब या प्रमाणित प्रति संलग्न क जाएगा।

(3) पुनरक्षण के लिए प्रत्येक अपल या आवेदन—

(क) अपीलार्थी या आवेदक का नाम और पता और, यथास्थिति, प्रत्यक्षियों के नाम और पते का भी विनिर्देश करेगा,

(ख) उग बात का उल्लेख करेगा कि वह आवेदन जिसके विरुद्ध अपल क गई है या जिसमें पुनरीक्षण किया जाता है, जिसके द्वारा किया गया था,

(ग) संक्षिप्त और विनिर्दिष्ट जणों के अधिनियमित उस आवेदन के जिसके विरुद्ध अपल क गई है या जिसको पुनरक्षण दिया जाता है, माध्यों के आपत सहित, आदेशों के आधारों को उपबोधित करेगा;

(घ) संक्षिप्त उस अनुलोप का उल्लेख करेगा जिसका अपीलार्थी या आवेदक दावा करता है, और

(क) उग आवेदन की जिसके विरुद्ध अपल क गई है या जिसे पुनरक्षण किया जाता है, तारख देगा।

(4) जहाँ—

(क) धारा 90 का उपधारा (2) के अधिनियमित अपल उपाय में विनिर्दिष्ट साठ दिनों के समाप्ति के पश्चात् क जाता है, या

(ख) धारा 92 का उपधारा (1) के अधिनियमित पुनरक्षण के लिए प्राप्त आवेदन उस तारख से जिसको वह विनिश्चय या आदेश जिससे आवेदन संबंधित है अपीलार्थी को संसूचित किया जाता है, तबले दिन का समाप्ति के पश्चात् किया जाता है,

तो उसके साथ एक शपथपत्र द्वारा एक अपीलार्थी या अपेक्षित अपेक्षित उन माध्यों को उपबोधित किया जाएगा जिन पर अपीलार्थी या आवेदक अपल या पुनरक्षण प्राधिकार का यह समाधान करने के लिए अवलम्ब लेना चाहता है कि उसके पास खण्ड (क) और (ख) में विनिर्दिष्ट सबध के अन्तर पुनरक्षण के लिए अपल या आवेदन न करने के लिए पर्याप्त हेतु था।

(5) पुनरक्षण के लिए आवेदन क अपल का प्राप्ति पर, अपल या पुनरक्षण प्राधिकार, यथास्थिति, उसका परीक्षा करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि—

(क) अपल या आवेदन प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को ऐसा करने का अधिकारिता है;

(ख) यह विहित समय मास के अन्तर किया गया है,

(ग) वह अधिनियमित और इन नियमों के तहत उपायों के अन्तर्गत है।

(6) अपल या पुनरक्षण प्राधिकार, अपीलार्थी या आवेदक से ऐसा करने का सूचना क प्राप्ति के पश्चात् दिनों के पश्चात् के अन्तर द्युति, यदि कोई हो, का उपचार करने के लिए या ऐसे अनिश्चित जानकारी, जो आवश्यक हो, देने के लिए पुनरक्षण के लिए अपेक्षा कर सकेगा यदि पुनरक्षण के लिए अपीलार्थी या आवेदक उस अपेक्षा के अन्तर प्रपेक्षित दृष्टियों का उपचार करने या अनिश्चित जानकारी देने में असमर्थ रहता है तो अपल या पुनरक्षण अपीलार्थी का जा सकेगा।

(7) अपल या पुनरक्षण प्राधिकार, धारा 90 या धारा 92 के अधिनियमित प्राप्ति करने के पूर्व, किम्. अधिनियमित अधिकार, से ऐसा करेगा—

वाहियों का नियमितता या पारित किसी निनिश्चय या उसमें किए गए किसी आदेश का सत्यता, वैधता या औचित्य के सत्यापन के प्रयोजन के लिए जांच या कार्यवाहियों का बाबत ऐसी अनिश्चित जानकारी अभिप्राप्त कर सकेगा। अपील या पुनराक्षण प्राधिकार ऐसा जांच या कार्यवाहियों से संबद्ध पक्षकारों से ऐसी जानकारी की अपेक्षा अभिप्राप्त कर सकेगा जो जांच या कार्यवाहों के अभिलेखों के परीक्षा के संदर्भ में आवश्यक है और अधस्त्य अधिकार से सूचना अभिप्राप्त की जा सकेगी।

(8) अपील या पुनराक्षण प्राधिकारों का गई जांच के आधार पर और जांच किए गए अभिलेखों के प्रतिनिर्देश से, पुनराक्षण के लिए अपील या आवेदक के संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो न्यायगत और व्यक्तिगत प्रत हो।

(9) धारा 90 या 92 का उपधारा (2) के अधीन अपील या पुनराक्षण प्राधिकार का प्रत्येक आदेश, लिखित रूप में होगा और वह अपेक्षार्थी या आवेदक को और ऐसे अन्य पक्षकारों को जो उस प्राधिकार का राय में उस निनिश्चय या आदेश द्वारा प्रभावित हो सकते हैं, और उस संबंध प्राधिकारों को जिसके आदेश के विरुद्ध पुनराक्षण के लिए अपील या आवेदन किया गया था, समूचित किया जाएगा।

39. पुनर्विलोकन के लिए आवेदन:—(1) धारा 93 के अधीन प्रत्येक आवेदन आपन के प्ररूप में होगा जिसमें संक्षिप्त और सुभिन्न शर्तों के अधीन ऐसे नए और महत्वपूर्ण तथ्यों को उपबोधित किया जाएगा जो, सम्यक् तत्परता बरतने के पश्चात्, उस समय आवेदक की जानकारी में नहीं थे और जो उसके द्वारा तब पेश नहीं किए जा सके थे जब आदेश किया गया था या गलती या त्रुटि अभिलेख में दृश्यमान था या अन्य कारणों से जिसके आधार पर पुनर्विलोकन चाहा गया है, इसके साथ साक्ष्य का एक आपन संलग्न किया जाएगा।

(2) आवेदन के साथ उस आदेश का जिसमें आवेदन संबद्ध है, मूल या प्रमाणित प्रति संलग्न का जाएगा।

(3) पुनर्विलोकन के लिए कोई आवेदन तब ग्रहण नहीं किया जाएगा, जब तक उसके साथ उतनी अनिश्चित प्रतियां संलग्न नहीं की जाती हैं जितने मूल आदेश में पक्षकार हैं।

(4) आवेदन जहां तक वह आवश्यक हो, अपील प्राधिकार द्वारा ऐसी रीति में निपटाया जाएगा जो ठीक नहीं। परन्तु किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे व्यक्ति को अपना अस्यावेदन करने का अवसर न दे दिया गया हो।

प्ररूप 1

[नियम 3 का उपनियम (1) देखिए]

..

बहुराज्य सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1984 के अधीन बहुराज्य सहकारी सोसाइटीज के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

सेवा में,

केन्द्रीय रजिस्ट्रार,
सहकारी सोसाइटियां

महोदय,

हम निम्नलिखित बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के लिए एक प्रस्ताव, नीचे उल्लिखित संलग्नकों के साथ प्रस्तुत करने हैं:

2. हम यह भी घोषण करने हैं कि इसके साथ दी गई जानकारी, जिसके अन्तर्गत संलग्नकों में दी गई जानकारी भी है, हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य

(क) प्रस्तावित बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का नाम:

(ख) रजिस्टर किया जाने वाला मुख्यालय और पता:

(ग) प्रवर्तन क्षेत्र:

(घ) मुख्य उद्देश्य:

(ङ) सोसाइटी के लिए बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1984 के अधीन रजिस्ट्रीकृत होना आवश्यक रूप में क्यों आवश्यक है:

(च) क्या कोई अन्य ऐसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी है जिसका प्रवर्तन क्षेत्र वही है और उद्देश्य तत्समान है:

- (छ) यदि सभी सदस्य व्यक्ति हैं तो प्रत्येक राज्य से उन व्यक्तियों की संख्या दीजिए जिन्होंने आवेदन पर हस्ताक्षर किए हैं :

राज्य का नाम

व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने आवेदन पर हस्ताक्षर किए हैं .

- (ज) आगे पत्र व्यवहार के प्रयोजन के लिए आवेदन का नाम और पता :

3 निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न हैं :

- (क)* बैंक का प्रमाणपत्र जिसमें प्रस्तावित बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के पक्ष में उस बैंक में जमा अतिशेष का उल्लेख किया गया है।

- (ख) एक स्वीय जिसमें यह स्पष्ट करने हुए ध्योरे दर्शाए गए हैं कि बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का कार्यकरण किस प्रकार आर्थिक रूप से सुव्यवहारा। इस सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित उपविधियों की चार प्रतियां साथ में भेज रहे हैं।

4. निम्नलिखित व्यक्ति उपविधियों में हस्ताक्षर करने के लिए और उनमें आवश्यक फेरफार करने के लिए भी प्राधिकृत हैं।

5. आवेदकों की निशानियां नीचे दी गई हैं :

क्रम नं.	नाम	यदि किसी निगमित निकाय का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो उस संस्था का नाम*	यदि आवेदक व्यक्ति है	आय	राष्ट्रिकता	वृत्ति
1	2	3	4	4क	4ख	4ग

राज्य का नाम	पता	शेयरपूँजी में अभिदाय की रकम	सोसाइटी या बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के प्रतिनिधि की दशा में, क्या वह उस सोसाइटी का अध्यक्ष/प्रधान या मुख्य कार्यपालक है	हस्ताक्षर
5	6	7	8	9

कार्यालय के प्रयोग के लिए

केन्द्रीय रजिस्ट्रार के कार्यालय में, द्वारा को रजिस्ट्री डाक से, या श्री से सीधा प्राप्त किया। आवेदन रजिस्टर में क्रम सं. पर पर दर्ज किया।

प्राप्तकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

..... सोसाइटी लिमिटेड (प्रस्तावित) के रजिस्ट्रीकरण के लिए तारीख को रजिस्ट्रीकरण प्रस्ताव सं., ऊपर निर्दिष्ट संलग्नकों सहित, से डाक से/सीधे प्राप्त किया।

केन्द्रीय रजिस्ट्रार

स्थान:

हस्ताक्षर और स्टाम्प

तारीख:

*यदि किसी सहकारी या किसी अन्य निगमित निकाय का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो प्रस्ताव की प्रति या मक्षम प्राधिकारी का प्राधिकारपत्र, जिसके द्वारा व्यक्ति को रजिस्ट्रीकरण आवेदन पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, संलग्न करें।

*रिक्त स्थान भरिए।

प्रारूप सं. 2

[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]

बहुराज्य सहकारी संस्थागतियों के रजिस्ट्रीकरण के लिए केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा प्राप्त किए गए आवेदनों का रजिस्टर

क्रम सं.	प्रस्तावित बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का नाम और मुख्य प्रस्तावक	पूरा पता	प्राप्त करने की तारीख और किस प्रकार प्राप्त हुआ	प्राप्ति स्वीकार की तारीख और निर्देश सं.
1	2	3	4	5

सं. और तारीख जिसको अनतिरिक्त जानकारी मांगी गई है	विहित तारीख जिस तक जानकारी मांगी गई है	तारीख जिसको अनतिरिक्त जानकारी प्राप्त हुई
6	7	8

यदि सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण छह मास के भीतर नहीं किया जाता है तो केन्द्रीय सरकार को भेजी गई रिपोर्ट की सं० और तारीख यदि रिपोर्ट भेजी गई है	रजिस्ट्रीकरण सं. और तारीख	इन्कार की सं. और तारीख	हस्ताक्षर	टिप्पणियाँ
9	10	11	12	13

अनुसूची

1. बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों के बोर्ड के निर्वाचनों के संचालन को धाबत प्रक्रिया—

इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, और धारा 35 की उपधारा (1) में केन्द्रीय सरकार की शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निविष्ट राष्ट्रीय सहकारी सोसाइटियों और ऐसा अन्य बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों या बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों के ऐसे वर्ग, जिन्हें केन्द्रीय सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा अधिसूचित करे, बोर्ड के सदस्यों या निर्वाचन ऐसे रिटनिंग आफिसरों द्वारा संचालित किए जाएंगे जो इस निमित्त केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त किए जाएं। ऐसे सोसाइटियों के निर्वाचन का संचालन इसमें इसके आगे उपबोधित रीति से किया जाएगा:—

2. निर्वाचन कार्यक्रम :

- (क) पदस्थ निदेशक बोर्ड अपनी पश्चाद्विधि की समाप्ति की तारीख से एक साठ दिन पहले अपना अधिवेशन करेगा और एक प्रस्थापना द्वारा अपने उत्तरवर्ती बोर्ड के निर्वाचन के संचालन के लिए साधारण निकाय का अधिवेशन आयोजित करने की तारीख समय और स्थान अवधारित करेगा। यह उपबंध ऐसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों की ओर धारा 48 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किए गए प्रशासक के आदेशानुसार में है, आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होगा।
- (ख) उप पैरा (क) में निविष्ट विनिश्चय को एक प्रति तुरन्त केन्द्रीय रजिस्ट्रार को भेजी जाएगी।
- (ग) केन्द्रीय रजिस्ट्रार, उप पैरा (ख) में निविष्ट विनिश्चय प्राप्त होने पर, धारा 35 की उपधारा (1) के अधीन एक रिटनिंग आफिसर नियुक्त करेगा। रिटनिंग आफिसर, इसके शांति पश्चात्, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य को साधारण अधिवेशन की तारीख, समय और स्थान का बाबत स्थानीय वितरण द्वारा या रजिस्ट्री डाक से सूचित करेगा। जहाँ अन्य सहकारी सोसाइटियों या बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों सदस्य हैं वहाँ रिटनिंग आफिसर ऐसा सोसाइटी से अपने अध्यक्ष या सभापति या मुख्य कार्यपालक का नाम, धारा 29 की उपधारा (3) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार प्रतिनिधि के रूप में, (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रतिनिधि कहा गया है) तथा सोसाइटी के बोर्ड का प्रस्थापना और अध्यक्ष, सभापति या मुख्य कार्यपालक के सम्यक् रूप से सत्यापित और सोसाइटी का मुद्रायुक्त हस्ताक्षरों के समूह में भेजने की मांग करेगा जिससे कि वे साधारण अधिवेशन के लिए नियत की गई तारीख से कम से कम ठीक 21 दिन पूर्व उसके पास पहुँच जाएं। यदि ऐसा सहकारी सोसाइटी या अन्य बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का कोई बोर्ड नहीं है तो उसका प्रशासक, वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, निविष्ट में और अपने हस्ताक्षर से रिटनिंग आफिसर को साधारण अधिवेशन के लिए नियत तारीख से कम से कम ठीक 21 दिन पूर्व यह सूचित करेगा कि साधारण अधिवेशन में वह ऐसा सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करेगा। यदि नियत तारीख तक, प्रत्यायोजित व्यक्ति का नाम सूचित करते हुए ऐसी कोई प्रस्थापना या संसूचना प्राप्त नहीं होती है या जहाँ प्रत्यायोजित व्यक्ति के नाम में किसी परिवर्तन की कोई संसूचना ऐसा तारीख के पश्चात् प्राप्त होती है तो वह सोसाइटी के सदस्यों प्रतिनिधियों की सूची में सम्मिलित करने के लिए स्वीकार नहीं का जाएगा। ऐसे प्रत्येक साधारण अधिवेशन के लिए, जिसमें चुनाव आयोजित किए जाएं, नई प्रस्थापनाएं अपेक्षित होंगी।

(घ) पदस्थ निदेशक बोर्ड या प्रशासक का यह कर्तव्य होगा कि वह सदस्यों के रजिस्ट्रार को और ऐसे अन्य रजिस्ट्रारों को जिनका रिटनिंग आफिसर द्वारा अपेक्षा की जाए, सूचित रखे और निर्वाचन के प्रयोजन के लिए साधारण अधिवेशन के लिए नियत की गई तारीख से 30 दिन पहले ऐसे अभिलेखों, रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रारों को रिटनिंग आफिसर को सौंप दें।

(ङ) निर्वाचन इस प्रयोजन के लिए बुलाए गए सोसाइटी के ऐसे साधारण अधिवेशन में किया जाएगा जिसमें सदस्यों को कम से कम 14 दिन का सूचना दी गई हो। ऐसे निर्वाचन तब होंगे जब कार्य सूची में सम्मिलित और सब अन्तर्विधियों पर विचार कर लिया जाए। निर्वाचनों के संचालन के लिए रिटनिंग आफिसर अधिवेशन का अध्यक्षता करेगा।

(च) साधारण अधिवेशन का सूचना सदस्यों को निम्नलिखित किसी रीति से भेजी जाएगी, अर्थात्:—

(i) स्थानीय वितरण द्वारा; या

(ii) रजिस्ट्री डाक द्वारा।

(छ) साधारण अधिवेशन का सूचना बहुराज्य सहकारी सोसाइटी और उसका शाखाओं, यदि कोई हैं, के सूचना पट्ट पर विपकाया जाएगा। सूचना में यह जानकारी होगी:—

(i) निर्वाचन द्वारा भी जाने वाला रजिस्ट्रारों का संख्या;

(ii) उस निर्वाचन क्षेत्र का (उपविधियों में विनिश्चित), जिससे सदस्यों का निर्वाचन किया जाना है, विस्तार;

(iii) बोर्ड की समस्या के लिए उप विधियों में विनिश्चित पात्रता संघों अर्थात्, यदि कोई हैं;

(iv) रिटनिंग आफिसर का नाम, वह तारीख, स्थान और अवधि जिसको, जहाँ और जिसके बीच सदस्यों द्वारा नामांकन पत्र फाइल किए जाएंगे। यह तारीख निर्वाचन के लिए नियत की गई तारीख से ठीक एक दिन से कम पूर्व की नहीं होगी या यदि वह दिन अवकाश का दिन है तो उसके पूर्ववर्ती दिन होगा जो लोक अवकाश का दिन न हो।

स्पष्टीकरण—इस उप पैरा के प्रयोजन के लिए “लोक अवकाश दिन” पद से वह दिन अभिप्रेत है जो परकाय्य लिखित अधिनियम, 1881 (1881 का 26) का धारा 25 के अधीन लोक अवकाश दिन घोषित किया गया है या वह दिन अभिप्रेत है जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा अपने कार्यालयों के लिए अवकाश दिन के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(v) वह तारीख जिसको और वह समय और स्थान जिस पर नामांकन पत्रों का समाप्ति की जाएगी,

(vi) नाम वापस लेने का तारीख और समय, और

(vii) वह तारीख जिसको, और वह स्थान जिस पर, तथा वह अवधि जिसके बीच, मतदान होगा।

3. सदस्यों/प्रतिनिधियों का सूचन का तैयारी :

(क) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी मतदान के लिए नियत तारीख के तीन दिन पूर्व उस तारीख को मत देने के पात्र सदस्यों को एक सूचन तैयार करेगा और सूचन का प्रतियाँ सोसाइटी के मुख्यालय और उसका सभी शाखाओं, यदि कोई हों, के बोर्ड

पक्षों पर विपका कर निर्वाचन के लिए नियत तारीख के 15 दिन से अग्रपुनः पूर्व, प्रकाशित की जाएगी। सूचना में यह विनिर्दिष्ट होगा :—

(i) सदस्य का प्रवेश सं., और नाम, पिता या पति का नाम, और व्यक्तिगत तथ्य की वशा में, ऐसे सदस्य का पता; तथा

(ii) प्रवेश सं., सोसाइटी का नाम, सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रस्तावित प्रतिनिधि का नाम, यदि सोसाइटी सदस्य है।

(ख) सोसाइटी सदस्य को, ऐसा फॉर्म का संवाह करने पर जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, सूचना की प्रति देगा। जहां कोई फॉर्म विनिर्दिष्ट नहीं है, गई हो वहां सोसाइटी को उपनिधियों में तथा प्राधिकृत व्यक्ति ऐसे सूचना पात्र रूप का रकम संवाह करने पर देगा।

4 उम्मीदवारों का नामांकन : (क) निर्वाचन के लिए उम्मीदवारों का नामांकन इस अनुसूची में सन्तान नामांकन प्रारूप में किया जाएगा जो रिटनिंग आफिसर या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा किसी भी सदस्य को आवेदन करने पर निशुल्क दिया जाएगा।

(ख) प्रत्येक नामांकन पत्र पर ऐसे दो सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे जिनके नाम सदस्यों/प्रतिनिधियों की सूची में सम्मिलित हैं। सदस्यों में से एक प्रारूप पर नामांकन के प्रस्तावक के रूप में हस्ताक्षर करेगा और दूसरा समर्थक के रूप में। नामांकन पत्र में उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षरित एक घोषणा भी होगी जिसमें निर्वाचन के लिए खड़े होने की उसकी राजमदो अभिव्यक्ति की गई हो।

(ग) प्रत्येक नामांकन पत्र स्वयं उम्मीदवार या उसके प्रस्तावक या समर्थक द्वारा स्वयं या रजिस्ट्री डाक से, पोस्टी सहित, रिटनिंग आफिसर को, या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार प्राधिकृत भेजा जाएगा कि वह उसके पास पैरा 2 (क) के अनुसार अधिवेशन की सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख और समय से पहले पहुंच सके। रिटनिंग आफिसर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई भी अधिकारी, जो नामांकन पत्र प्राप्त करता है, नामांकन पत्र पर उसका क्रम संख्यांक दर्ज करेगा और वह तारीख और समय, जब नामांकन पत्र उससे प्राप्त किया है, प्रमाणित करेगा और नामांकन पत्र को प्राप्ति-स्वीकृति तत्काल लिखित में देगा, यदि नामांकन पत्र व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया जाता है, और उस पर सोसाइटी का सील भी लगाई जाएगा। रिटनिंग आफिसर नामांकन पत्र प्राप्ति के लिए नियत समय समाप्त होने पर उनके द्वारा प्राप्त नामांकनों का सूचा तैयार करेगा और सोसाइटी के सूचना पत्र पर प्रदर्शित करेगा। कोई भी नामांकन पत्र जो उसकी प्राप्ति के लिए नियत तारीख और समय पर पर या उसके पहले परिदत्त नहीं किया जाता या प्राप्त नहीं होता रद्द किया जाएगा।

(घ) किसी व्यक्ति को, बोर्ड में कोई पद धरने के लिए निर्वाचन में उम्मीदवार के रूप में नामांकन नहीं किया जाएगा यदि—

(i) वह मतदान के लिए पात्र नहीं है ;

(ii) वह अधिनियम के उपबंधों के अधीन सदस्य / होने के लिए या इन नियमों के अधिन बोर्ड का सदस्य होने के लिए निरहित है और

(iii) उसके पास बोर्ड के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए सोसाइटी का उप विधियों में विनिर्दिष्ट आवश्यक अहंताएं नहीं हैं।

5. नामांकन पत्रों का संवधा :— (क) (i) रिटनिंग आफिसर, नामांकन पत्रों को प्राप्ति के लिए नियत दिन को, नियत समय पर नामांकन पत्रों को संवेक्षा आरम्भ करेगा। उम्मीदवार या प्रत्येक उम्मीदवार को प्रस्तावक या समर्थक उस समय और स्थान पर उपस्थित रह सकता है जब नामांकन पत्रों का संवेक्षा का जात है।

(ii) रिटनिंग आफिसर नामांकन पत्र को परीक्षा करेगा और उन आक्षेपों का विनिश्चय करेगा जो नामांकन का बाधक किमो उम्मीदवार या उसके प्रस्तावक या समर्थक द्वारा किए जाते हैं और, ऐसे आक्षेप पर, या स्वप्रेरणा से, तथा ऐमा संश्लिष्ट जांच के पश्चात्, जैसा वह आवश्यक सम्भत्ता है किमो नामांकन पत्र को रद्द कर सकता है :

परन्तु किमो उम्मीदवार का नामांकन पत्र केवल इस आधार पर रद्द नहीं किया जाएगा कि उससे उसके नाम का या उसके प्रस्तावकर्ता या समर्थक के नाम का वर्णन या उम्मीदवार, उसके प्रस्तावक या समर्थक से संबंधित कोई बिनिर्दिष्टता, जैसी पैरा 3 (क) में निर्दिष्ट सदस्यों के सूचा में तथा प्रविष्टि के अनुसार असत्य हैं यदि उस उम्मीदवार, प्रस्तावक या समर्थक का पहचान उचित सदेह के पत्रे निश्चित हो जात है।

(iii) रिटनिंग आफिसर प्रत्येक नामांकन पत्र पर उसे स्वीकार या रद्द करने का अपना विनिश्चय पुष्ठाकिन करेगा और यदि नामांकन पत्र रद्द किया जाता है तो वह ऐसे रद्दकरण के अपने आधारों का संक्षिप्त कथन लिखित रूप में दर्ज करेगा।

(iv) रिटनिंग आफिसर कार्यवाहियों का कोई भी स्थगत अनुशात नहीं करेगा सिवाय तब जब कार्यवाहियों में वसने या दंगे के कारण, या ऐसे कारणों से जो उसके निवेक्षण से परे हैं, कोई विघटन या व्यवधान पड़ जाता है।

(v) रिटनिंग आफिसर द्वारा यथा विनिर्दिष्ट विधिमान्य नामांकनों का सूचा सोसाइटी के सूचना पत्र पर प्रकाशित का जाएगा। सूचा में उम्मीदवारों के वर्णानुक्रम से नाम और जैसा कि नामांकन पत्र में दिए गए हों, उसी दिन जिस दिन नामांकन पत्र का संवेक्षा पूर्ण होता है, अंग्रेजी में प्रकाशित किए जाएंगे।

(ख) कोई भी उम्मीदवार अपने हस्ताक्षर से, लिखित सूचना द्वारा, जो उसके द्वारा स्वयं या उसके प्रस्तावक या समर्थक द्वारा नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात्, किमो भी समय, किन्तु पैरा 2 (क) (vi) में विनिर्दिष्ट नाम वापस की तारीख और समय से पूर्व परिदत्त का जाता है, अपना उम्मीदवार का वापस ले सकता है। उम्मीदवार, वापस का सूचना देने के पश्चात् वापस नहीं नहीं जा जा सकेगा।

6. मतदान :—(क) यदि किसी क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्र के लिए, जिसके लिए निर्वाचन आयोजित किया जाता जाता है, उन उम्मीदवारों का संख्या जिनके नामांकन पत्र विधिमान्य घोषित किए गए हैं, उस क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचित किए जाने वाले उम्मीदवारों का संख्या से अधिक नहीं है, तो रिटनिंग आफिसर निर्वाचन के प्रयोजन

के लिए बुलाए गए साधारण अधिवेशन में उन्हें बोर्ड द्वारा सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित करेगा। यदि उन उम्मीदवारों के संख्या जिनके नामांकन विधिमान्य हैं, किसी क्षम या निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचित किए जाने वाले संख्या से अधिक है तो रिटनिंग आफिसर इस प्रयोजन के लिए नियत की गई तारीख को और समय पर मतदान के लिए व्यवस्था करेगा। रिटनिंग आफिसर उतने मतदान अधिकारों नियुक्त कर सकेगा जितने वह मतदान कराने के लिए आवश्यक समझे।

(ख) निर्वाचन लड़ने वाला उम्मीदवार रिटनिंग आफिसर को पत्र द्वारा मतदान के स्थान पर उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए, मतदानाग्राहों को पहचान हेतु और मतदान पर ध्यान रखने के लिए अधिकारों नियुक्त कर सकता है। ऐसे पत्र में संबंधित अधिकारों के लिखित सन्मति होना चाहिए।

(ग) जिस व्यक्ति द्वारा उस स्थान पर, जहाँ निर्वाचन का संचालन किया जाना है, मतदान का संचालन प्रतिनिधित्व होगा।

(घ) रिटनिंग आफिसर मतदान के प्रारूप से ठीक पूर्व, उन व्यक्तियों को जो उस समय उपस्थित हों, खाली मतदान पेट को दिखाएगा और तब उसमें ताला लगाएगा और उस पर अपने मुद्रा ऐसा रूति से लगाएगा जिससे कि मुद्रा को साँझे बिना उसे खोलने से निवारित किया जा सके। उम्मीदवार या उसका अधिकारी भ, यदि वह ऐसा बाँछा करता है तो, उस पर अपना मुद्रा लगा सकता है।

(ङ) ऐसे प्रत्येक सदस्य/प्रतिनिधि को जो मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग करने के इच्छा करता है, एक मतदान पत्र दिया जाएगा जिसमें लड़ रहे उम्मीदवारों के नाम घणानुक्रम से, सुविधानुसार, या तो मुद्रित होंगे या टाइप या साइक्लोस्टाइल होंगे। मतदान पत्र पर सोमार्हटों के मुद्रा लगें होंगे और रिटनिंग आफिसर के हस्ताक्षर होंगे तथा मतदान के लिए उन व्यक्ति/व्यक्तियों के नाम या नामों के सामने, जिनके पक्ष में वह मत देना चाहता है, "X" चिन्ह लगाने के लिए एक स्तम्भ होगा।

(च) प्रत्येक मतदान स्थान पर, और यदि किसी स्थान पर एक से अधिक मतदान केंद्र हैं, प्रत्येक मतदान केंद्र पर, एक पृथक् कक्ष होगा ताकि सदस्य / प्रतिनिधि गोपनीय रूप से अपना मत दे सके।

(छ) प्रत्येक व्यक्ति जो मतदान करना चाहता है, मतदान स्थान में एक पहचान पत्र के साथ यदि कोई है, जो उसे दिया गया हो, प्रवेश करेगा। मतदान अधिकारों मतदान स्थान में मत देने के पक्ष सदस्य / प्रतिनिधि के सूचक के प्रति निर्देश में, जो उसे दी गई हो, सदस्य से प्रश्न पूछकर उसकी पहचान करेगा। यदि सदस्य को पहचान के बारे में मतदान अधिकारों का समाधान हो जाता है और यदि मतदान स्थान पर उपस्थित किसी उम्मीदवार या मतदान अधिकारों द्वारा आक्षेप नहीं किया जाता है तो मतदान अधिकारों उसे एक मतदान पत्र देगा। ऐसा मतदान पत्र प्राप्त होने पर सदस्य इस प्रयोजन के लिए अलग बनाए गए मतदान कक्ष में जाएगा और उस उम्मीदवार या उन उम्मीदवारों के नामों के सामने, जिनके पक्ष में वह मत देना है, "X" का चिन्ह लगाकर वह उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को दर्शाएगा, मतदान पत्र को मतदान पेट में, जो इस प्रयोजन के लिए रखा गई हो, अत्यन्त गोपनीयता के साथ डालेगा। यदि अन्धपन या अन्य गारंरिक असमर्थता या अशिक्षित होने के कारण कोई सदस्य मतदान पत्र पर चिन्ह लगाने में असमर्थ है तो मतदान अधिकारों, और जहाँ कोई मतदान अधिकारों नियुक्त नहीं किया गया है वह रिटनिंग आफिसर, उनसे उस उम्मीदवार या उम्मीदवारों के नाम पूछेगा जिनके पक्ष में वह मतदान करना चाहता है, उनके और से, "X" चिन्ह लगाएगा और मतदान पत्र को मतदान पेट में डालेगा।

(ज) (i) प्रत्येक सदस्य जिसका नाम मतदान अधिकारों को दी गई नमस्त्रों/प्रतिनिधियों का सूचक में दर्श है, तब तक मतदान का वृकदार है जब तक उसका पहचान का बाबत उम्मीदवार का उसके अधिकारों द्वारा आक्षेप नहीं किया जाता है। यदि किसी सदस्य का पहचान के बारे में इस प्रकार आक्षेप किया जाता है या यदि मतदान अधिकारों को उचित संदेह है तो वह मामले को रिटनिंग आफिसर को निर्दिष्ट करेगा जो सक्षम जांच करेगा और सोमार्हटों के पुस्तकों के प्रति निर्देश से उस प्रश्न का निश्चय करेगा।

(ii) रिटनिंग आफिसर किसी सदस्य का पहचान के बारे में उम्मीदवार या उसके मतदान अधिकारों द्वारा किसी आक्षेप को तब तक तक ग्रहण नहीं करेगा जब तक वह व्यक्ति, जो आक्षेप करता है ऐसे प्रत्येक मत के लिए फंस के 5 रुपये (पाँच रुपये) का तकद संशय नहीं करता है। तत्पश्चात् रिटनिंग आफिसर आक्षेप ग्रहण करेगा और उस सदस्य को मत देने के लिए आया है, यथास्थिति अपना अग्रगण्य निशान या हस्ताक्षर, अपना पहचान का घोषणा पर लगाने के लिए कहेगा यदि वह ऐसा करने में इकार करता है तो सदस्य को मतदान करने का अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके विपरीत यदि ऐसे संक्षिप्त जांच के परिणामस्वरूप सदस्य का पहचान रिटनिंग आफिसर के सतोषप्रद रूप में निश्चित हो जाती है तो मतदान अधिकारों मत पत्र जारी करेगा और तब सदस्य को मतदान करने का अनुमति दी जाएगी। ऐसे मामलों में संदेह फंस जन्म कर ली जाएगी। मतदान के घंटे में, रिटनिंग आफिसर संग्रह को, यदि आक्षेप फंस का उन व्यक्तियों को जिन्होंने आक्षेप किया है वापस का गई फंस का और सोमार्हटों के पक्ष में जन्म का गई फंस का हिमाव देगा और प्रत्येक मामले में संक्षिप्त जांच के बाद किए गए अपने निनिश्चय को बाबत एक संक्षिप्त टिप्पण मा देगा।

(झ) (अ) यदि मतदान के किसी अनुक्रम पर दंगे या बलबे के कारण कार्यवाहियों में कोई विघटन या व्यवधान पड़ता है या ऐसे निवाचन में यदि किसी पर्याप्त कारण से मतदान कराना सम्भव नहीं है, तो रिटनिंग आफिसर को, ऐसा कारवाई करने के लिए अपने कार्यों को लेखबद्ध करने के पश्चात् मतदान रोक देने की शक्ति होगी।

(आ) जहाँ मतदान खंड (क) के अधीन रोक दिया जाता है या जहाँ मतदानपेटियों के नष्ट हो जाने या उनकी हानि हो जाने के कारण या किसी अन्य पर्याप्त कारण से मतपत्रों का गणना प्रत्यक्ष हो जाती है वहाँ रिटनिंग आफिसर, सोमार्हटों को कार्यवृत्त पुस्तिका में ऐसा कारवाई के कारणों का लेखबद्ध करने के पश्चात् मतदान रोक देगा।

(ब) मतदान के लिए नियत अवधि के पश्चात् किसी मतदाता को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा; किन्तु वह मतदाता जो मतदान को अवधि की समाप्ति के पूर्व उस परिसर में प्रवेश कर लेता है जहाँ मतदान पत्र आरंभ किए जा रहे हैं तो उसे मतदान पत्र जारी किया जाएगा और मतदान करने दिया जाएगा।

(ट) मत पत्र को गणना मतदान का समाप्ति के तुरन्त पश्चात् का जाएगा। यदि यह रिटनिंग आफिसर के निवेदन के परे किसी कारणों से सम्भव नहीं है तो मतदान पेटियों को रिटनिंग आफिसर और लड़ने वाले उम्मीदवारों या उनके अधिकारियों को मुद्रा से, यदि वे ऐसा बाँछा करते हैं तो, संलग्न किया जाएगा, और गुरक्षित अभिरक्षा के लिए सोमार्हटों में जमा कर दिया जाएगा। रिटनिंग आफिसर तब उपस्थित उम्मीदवारों या उनके अधिकारियों के समक्ष वह समय और स्थान घोषित करेगा जब और जहाँ गणना आगे किता दित आरम्भ का जाएगा और उसे लिखित में भी संसूचित करेगा। मतों को गणना रिटनिंग आफिसर द्वारा या उसके अधीन के अधीन की जाएगी। प्रत्येक व्यस्व-

वार और उसके प्राधिकृत अधिकारी का गणना के समय उपस्थित रहने का अधिकार होगा। किन्तु गणना के समय किम्, उम्मीदवार या उसके अधिकारी का अनुपस्थिति से गणना या गिटनिंग आफिसर द्वारा परिणामों का घोषणा निकाल नहीं हो जायेगा।

7 साधारण -- (क) मतदान पत्र गिटनिंग आफिसर द्वारा अस्वकार कर लिया जाएगा यदि --

- (i) उस पर कोई ऐसा चिह्न या लिखावट है जिससे मतदान करने वाले सदस्य का पहचान की जा सकता है, या
- (ii) उस पर सोसाइटी के सूत्र या गिटनिंग आफिसर के हस्ताक्षर नहीं है; या
- (iii) उस पर मत प्रकट करने वाला चिह्न ऐसे रीति से लगाया गया है जिसके कारण यह संदेहप्रद हो जाता है कि मत किम् उम्मीदवार के पक्ष में दिया गया है; या
- (iv) उसे इस प्रकार से नकलान पहुँचाया गया है या बिगारा गया है कि अस्वकार मत के रूप में उसका पहचान निश्चित नहीं हो जा सकता है।

(ख) यदि मतों का गणना पूरा हो जाने के पश्चात् किसी उम्मीदवारों के बीच मतों का संख्या बराबर पाई जाती है और एक मत जोड़ देने से उन उम्मीदवारों में से किसी को निर्वाचित घोषित किया जा सकता है तो गिटनिंग आफिसर ऐसे उम्मीदवार के बीच लाट द्वारा तुरन्त बिनियोज्य करेगा और इस प्रकार से अक्षर होगा मानो उस उम्मीदवार ने, जिसके पक्ष में लाट पड़ता है, अनिश्चित मत प्राप्त किया था और उसे निर्वाचित घोषित करेगा।

(ग) जब गिटनिंग आफिसर मतों का गणना पूरा कर के पश्चात् मतदान के परिणामों का एक विवरण तैयार करेगा और तुरन्त परिणाम घोषित करेगा। गिटनिंग आफिसर, इसके तुरन्त पश्चात्, निर्वाचन का कार्यवाहियों का एक विस्तृत रिपोर्ट लेखबद्ध करेगा जो सोसाइटी के अधिकारियों का भाग होगा और सब पर लिखकर होगा। ऐसा रिपोर्ट को एक प्रति और मतदान के परिणामों का एक प्रति गिटनिंग आफिसर द्वारा केन्द्रिय रजिस्ट्रार को भेजा जाएगा।

8. पैरा 1 में निर्दिष्ट सोसाइटियों से भिन्न बहुराज्य सहाकारी सोसाइटियों के बोर्ड के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया (1) ऐसी बहुराज्य सहाकारी सोसाइटी, जो पैरा 1 के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं है, के बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन हृथ उठाकर किया जाएगा।

(2) निर्वाचन इस प्रयोजन के लिए बुलाए गए बहुराज्य सहाकारी सोसाइटी के साधारण अधिवेशन में किया जाएगा जिसकी सदस्यों का कम से कम ठीक 14 दिन की सूचना दी जाएगी। साधारण अधिवेशन की सूचना सदस्यों को पैरा 2 के उप-पैरा (ख) में निर्दिष्ट किसी रीति में दी जाएगी और उसमें यह जानकारी होगी:--

(क) निर्वाचन द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या :-

(ख) वह क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्र, यदि कोई है, जिससे बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचित किया जाना है; और

(ग) वह तारीख जिसका, वह स्थान जिस पर और वह अवधि जिसमें निर्वाचन किए जाएंगे।

(3) निदेशक बोर्ड या धारा 48 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया प्रशासक या प्रशासकगण, उस तारीख से जिसका निर्वाचन होता है, 30 दिन पूर्व उस तारीख का पार्याप्त व्यष्टिक सदस्यों और सदस्य सोसाइटियों के प्रतिनिधियों की एक सूची तैयार करेगा और उसकी एक

प्रति निर्वाचन के लिए नियत तारीख से कम से कम 15 दिन पूर्व सोसाइटी के सूचना पट्ट पर चिपकाएगा। उन सूची की एक प्रति सोसाइटी द्वारा किसी भी सदस्य को ऐसी फीस का संवाय करने पर, जैसी बोर्ड या प्रशासक द्वारा विनिश्चित की जाए, दी जाएगी। जहाँ कोई फीस विनिश्चित नहीं की गई हो, वहाँ सोसाइटी का महापति/अध्यक्ष या प्रशासक, ऐसी सूची 2 रुपए का संवाय किए जाने पर देगा।

(4) इस अनुसूची में किसी बात के होते हुए भी महापति/अध्यक्ष या उपमहापति/उपाध्यक्ष, यदि वे बोर्ड के निर्वाचन में भाग लेने वाले उम्मीदवार नहीं हैं तो, अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा। यदि वे बोर्ड के निर्वाचन में भाग ले रहे हैं तो साधारण निकाय किसी एक सदस्य को जो बोर्ड के निर्वाचन में भाग लेने वाला उम्मीदवार नहीं है, निर्वाचनों के संचालन के लिए अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित करेगा।

परन्तु ऐसी सोसाइटी की बाबत जो इस नियम के अन्तर्गत आती है और जिसके लिए धारा 48 की उपधारा (1) के अधीन प्रशासक नियुक्त किया गया है, अधिवेशन का अध्यक्ष प्रशासक होगा।

(5) निर्वाचन के लिए उम्मीदवारों का नामांकन अधिवेशन में किया जाएगा। अधिवेशन का अध्यक्ष आक्षेपों का, जो नामांकन के समय किए जाते हैं, ऐसी संज्ञित जांच करने के पश्चात् जैसी वह आवश्यक समझता है, विनिश्चय करेगा और विधिमानी नामांकनों के अनुसार उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करेगा।

(6) यदि ऐसे किसी क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्र के लिए जिसके लिए निर्वाचन आयोजित किया जाना है, उन उम्मीदवारों की संख्या जिनकी बाबत विधिमानी नामांकनों की घोषणा की गई है, उन उम्मीदवारों की संख्या से अधिक नहीं है जो कि उस क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्र के लिए, निर्वाचित किए जाएंगे तो उन उम्मीदवारों को, जिनकी बाबत विधिमानी नामांकन घोषित किए गए हैं, उस क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्र के लिए, निर्वाचित किया गया समझा जाएगा और अधिवेशन का अध्यक्ष इस आशा की घोषणा करेगा। यदि उन उम्मीदवारों की संख्या जिनकी बाबत किसी क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्र के लिए विधिमानी नामांकन घोषित किए गए हैं, निश्चित किए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या से अधिक है तो मतदान किया जाएगा और अध्यक्ष जब लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम पढ़कर सुनाएगा। तत्पश्चात् वह ऐसे प्रत्येक उम्मीदवार का पक्ष और विपक्ष में मतदान किए गए मतपत्रों की संख्या दर्ज करेगा जो कि या तो हृथ उठाकर या मतदान पत्र द्वारा अमिनिश्चित की जाएगी और उसे सोसाइटी की कार्यवृत्त पुस्तिका में लेखबद्ध करेगा। अध्यक्ष प्रत्येक उम्मीदवार के पक्ष में दिए गए मतों की संख्या और निर्वाचन का परिणाम घोषित करेगा जो सोसाइटी की कार्यवृत्त पुस्तिका में लेखबद्ध किए जाएंगे और उसके द्वारा सत्यापित किए जाएंगे।

(7) जहाँ साधारण निकाय के सदस्यों द्वारा गुप्त मतदान की मांग की जाती है वहाँ इस मांग के औपचारिक प्रस्ताव पर मत लिए जाएंगे और उसे स्वीकार किया जाएगा। अधिवेशन कुछ समय के लिए स्थगित हो जाएगा जिससे कि अध्यक्ष गुप्त मतदान के लिए व्यवस्था करने में समर्थ हो सके।

गणना के पश्चात् साधारण निकाय का अधिवेशन पुनः आरम्भ होगा जिसमें निर्वाचन का परिणाम पैरा 8 के खण्ड (7) के अनुसार घोषित किया जाएगा।

9. उन सोसाइटियों के बोर्डों के निर्वाचन जो सदस्यों की अध्यक्षता पर गिटनिंग आफिसर द्वारा संचालित किए जाते हैं। पैरा 8 के उप-पैरा (1) में किसी बात के होते हुए भी, किसी बहुराज्य सहाकारी सोसाइटी की सदस्य सूची पर और प्राप्त सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम एक-बटा-पाँच सदस्यों से, साठ दिन अग्रिम में ऐसी अध्यक्षता प्राप्त होने पर कि निर्वाचन के संचालन के लिए गिटनिंग आफिसर नियुक्त किया जाए, केन्द्रिय रजिस्ट्रार पैरा 2 में 7 तक में

विनिर्दिष्ट रीति में निर्वाचन का संचालन करने के लिए एक रिटनिंग आफिसर नियुक्त करेगा।

10 पदधारियों का निर्वाचन.—(1) जैसे ही बॉर्ड के सदस्य निर्वाचित कर लिए जाते हैं, पैरा 1, 2 और 9 में निर्दिष्ट रिटनिंग आफिसर या पैरा 8 में निर्दिष्ट प्रधान/अध्यक्ष, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की उप-विधियों में सूचना की अवधि विनिर्दिष्ट होने हुए भी, सभापति/अध्यक्ष, उप-सभापति/उपाध्यक्ष या सोसाइटी के अन्य नव-निर्वाचित पदधारियों के, वे किसी भी नाम से जान हों, निर्वाचन के प्रयोजन के लिए नवगठित बॉर्ड का अधि-वेशन बुलाएगा। बॉर्ड के ऐसे अधिवेशन में तब तक कार्यवाही नहीं होगी जब तक नवगठित बॉर्ड के सदस्यों की संख्या का बहुमत उपस्थित न हो।

(2) पैरा 8 में निर्दिष्ट सभापति/अध्यक्ष द्वारा इस प्रकार बुलाए गए अधिवेशन में, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के नवगठित बॉर्ड के सदस्य अपने बीच से से एक सदस्य निर्वाचित करेंगे, जो किसी पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने वाला उम्मीदवार नहीं हो, जो निर्वाचनों के संचालन के लिए अधिवेशन का अध्यक्ष होगा। ऐसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के पदधारियों का निर्वाचन तब तक हाथ उठाकर होगा जब तक मतदान की भाग नहीं की जाती और उस वृत्त में बहु गुण मतदान द्वारा किया जाएगा।

(3) पैरा 1 और 9 में निर्दिष्ट सोसाइटी के पदधारियों का निर्वाचन केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त किए गए रिटनिंग आफिसर द्वारा संचालित किया जाएगा। ऐसे मामलों में निर्वाचन के लिए उम्मीदवारों का नामांकन नवगठित निदेशक बॉर्ड के उस अधिवेशन में किया जाएगा। रिटनिंग आफिसर उस समय किए गए आक्षेपों का, यदि कोई है, ऐसी संज्ञित जांच करने के पश्चात् जो बहु आवश्यक समझता है, विनिश्चय करेगा और विधिमार्ग नामांकनों की घोषणा करेगा।

(4) यदि किसी ऐसे पद के लिए जिसके लिए निर्वाचन आयोजित किए जाने पर, उन उम्मीदवारों की संख्या जिनकी बाबत विधिमार्ग नामांकनों की घोषणा की गई है, उस पद के लिए निर्वाचित किए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या से अधिक नहीं है तो उन उम्मीदवारों को, जिनकी बाबत विधिमार्ग नामांकन घोषित किए गए हैं, उस पद के लिए निर्वाचित समझा जाएगा और रिटनिंग आफिसर इस आशय की घोषणा करेगा। यदि उन उम्मीदवारों की संख्या, जिनकी बाबत किसी पद के लिए विधिमार्ग नामांकनों की घोषणा की गई है, निर्वाचित किए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या से अधिक है तो रिटनिंग आफिसर मतदान कराएगा। रिटनिंग आफिसर तत्पश्चात् प्रत्येक उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या की और निर्वाचन के परिणाम की घोषणा करेगा जो उसके द्वारा लेखबद्ध भी की जाएगी।

11. संचालित निर्वाचनों के अभिलेख की अनिश्चिता.— निर्वाचन के परिणाम की घोषणा करने के पश्चात्, पैरा 1, 9 और 10 में निर्दिष्ट रिटनिंग आफिसर या पैरा 8 के अधीन अधिवेशन का अध्यक्ष, निदेशक बॉर्ड के सदस्यों और पदधारियों के निर्वाचन से संबंधित मतदान पत्रों और अभिलेखों को, यदि कोई है, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के मुख्य कार्यपालक को, सीलबंद लिफाफे में सौंप देगा। सोसाइटी का मुख्य कार्यपालक उन्हें निर्वाचन की तारीख से छह मास की अवधि तक या ऐसे समय तक जब तक निर्वाचन की बाबत दाखिल किया गया कोई विवाद या अपील का निपटारा नहीं कर दिया जाता, दोनों में से जो भी अवधि पश्चात्तवर्ती हो, सुरक्षित रूप से रखे जाएंगे और तत्पश्चात् सट्ट कर दिए जाएंगे।

नामांकन पत्र

[पैरा 4 (क) देखिए]

1. बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का नाम और पता :

2. व्यक्ति-सदस्य की वृत्त में उम्मीदवार का नाम/प्रतिनिधि का नाम और वह सदस्य सहकारी सोसाइटी या बहुराज्य सहकारी सोसाइटी जिसका वह प्रतिनिधित्व कर रहा है :

3. सदस्यों के रजिस्ट्रार में क्रम सं. :

4. पिता या पति का नाम (व्यक्ति-सदस्य की वृत्त में) :

5. पता :

6. यदि प्रस्तावक व्यक्ति-सदस्य है तो प्रस्तावक का नाम और यदि प्रस्तावक सोसाइटी का प्रतिनिधि है तो सोसाइटी और प्रतिनिधि के नाम

7. सदस्यों के रजिस्ट्रार में प्रस्तावक का क्रम संख्या :

8. प्रस्तावक के हस्ताक्षर :

9. व्यक्ति-सदस्य की वृत्त में समर्थक का नाम और यदि समर्थक सोसाइटी का प्रतिनिधि है तो सोसाइटी तथा प्रतिनिधि का नाम :

10. सदस्यों के रजिस्ट्रार में समर्थक का क्रम संख्या :

11. समर्थक के हस्ताक्षर :

उम्मीदवार की घोषणा

मैं घोषणा करता हूँ कि मैं निर्वाचन में खड़े होने का इच्छुक हूँ और मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं अधिनियम तथा नियमों और बहुराज्य सोसाइटी की उपविधियों के अनुसार बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के बॉर्ड की सदस्यता से निर्वाचित नहीं हूँ।

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

रिटनिंग आफिसर का पृष्ठांकन

यह नामांकन पत्र पर मेरे समक्ष व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया गया है पर बड़े रजिस्ट्री डाक में प्राप्त हुआ है।

स्थान:

रिटनिंग आफिसर के या उसके द्वारा प्राधिकृत

तारीख :

व्यक्ति के हस्ताक्षर

[सं. एन. 11012/1/85-एन एण्ड एम]

के. एन. अद्वैतारिष्वरन, अपर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE & RURAL DEVELOPMENT

(Department of Agriculture and Cooperation)

New Delhi, the 16th September, 1985

G.S.R. 738(E).—In exercise of the powers conferred by section 109 of the Multi-State Co-operative Societies Act 1984 (51 of 1984), the Central Government hereby make the following rules, namely :—

THE MULTI-STATE CO-OPERATIVE SOCIETIES RULES, 1985

CHAPTER I PRELIMINARY

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Multi-State Co-operative Societies (Registration, Membership, Direction and Management, Settlement of Disputes Appeal and Revision) Rules, 1985

(2) These rules shall come into force from the Sixteenth day of September, 1985.

2. Definition : In these rules, unless the context otherwise requires :—

- (i) "Act" means the Multi-state Co-operative Societies Act, 1984 (51 of 1984).
- (ii) "Form" means a form appended to these rules.
- (iii) "general meeting" means a meeting of the general body including a representative general body referred to in section 29.
- (iv) "Section" means a section of the Act.
- (v) "Schedule" means Schedule appended to these rules.
- (vi) Words and expressions defined in the Act and used but not defined in these rules shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

CHAPTER II REGISTRATION

3. Application for registration.—(1) An application for registration of a multi-state Co-operative Society under sub-section (1) of section 6 shall be made in Form I and shall, subject to the provisions of sub-section (2) of section 6 and sub-rules (2) and (3) be signed by the applicants and be accompanied by :

- (a) four copies of the proposed bye-laws of the multi-State co-operative society, duly signed by each of the persons who sign the application for registration;
- (b) a list of persons who have contributed to the share capital, together with the amount contributed by each of them, and the entrance fee paid by them;
- (c) a certificate from the bank or banks stating the credit balance in favour of the proposed multi-State co-operative society;

- (d) a scheme showing the details explaining how the working of the multi-State co-operative society will be economically sound;
- (e) certified copy of the resolution of the promoters which shall specify the name and address of one of the applicants to whom the Central Registrar may address correspondence under the rules before registration and dispatch or hand over registration documents.

(2) Where any member of a multi-State co-operative society to be registered is a multi-State co-operative society or a co-operative society the chairman or chief executive of such multi-State co-operative society or co-operative society, as the case may be, shall be authorised by that board by a resolution, to sign the application for registration and bye-laws on its behalf, and a copy of such resolution shall be appended to the application.

(3) Where any member of multi-State co-operative society to be registered is a Government's company, a corporate body or a society registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) such member shall duly authorise any person to sign the application for registration and the bye-laws on its behalf and a copy of such resolution giving such authority shall be appended to the application.

(4) A copy of the resolution indicating the name of one or more applicants, who are authorised to make alterations or additions to the proposed bye-laws submitted with the application, as may be suggested by the Central Registrar, shall be submitted.

(5) The application shall either be sent by registered post or delivered by hand to the Central Registrar.

4. Registration.—(1) On receipt of an application under rule 3, the Central Registrar shall enter particulars of the application in the register of applications to be maintained in Form II, give a serial number to the application and issue a receipt in acknowledgement thereof.

(2) If the Central Registrar is satisfied that the proposed multi-State co-operative society has complied with the requirements of the Act and the rules, he may register the society and its bye-laws.

(3) Where the Central Registrar registers a multi-State co-operative society, he shall issue to the said society a certificate of registration signed by him and bearing his official seal containing registration number and date of registration of the said society. The Central Registrar shall also issue, along with the certificate of registration, a certified copy of the bye-laws, as approved and registered by him, which shall be the registered bye-laws of the said society for the time being in force.

5. Extension of period of registration of societies and bye-laws, etc.—The Central Government may, on the report of the Central Registrar, allow such further period not exceeding six months for registration of :—

- (i) the multi-State co-operative society under proviso to sub-section (3) of section 7;

- (ii) the amendment of bye-laws of the multi-State co-operative society under Proviso to sub-section (2) of section 9; and
- (iii) the amendment of bye-laws extending the jurisdiction of the co-operative society under proviso to sub-section (2) of section 18.

6. Refusal of registration.—Where the Central Registrar refuses to register a multi-State co-operative society under sub-section (2) of section 7, he shall communicate the order of refusal together with reasons therefor to the person authorised under clause (e) of sub rule (1) of rule 3 to the said society.

7. Subject matter of bye-laws.—The multi-State co-operative society may make bye-laws in respect of the following matters :—

- (i) the name and registered address of the multi-State co-operative society and its branches;
- (ii) the area of operation;
- (iii) the objects for which the multi-State co-operative society is established and the purpose for which its funds may be applied;
- (iv) the terms and qualifications for admission and withdrawal of membership;
- (v) the privileges, rights, duties and liabilities of members including nominal members :

Provided that the nominal members shall not be entitled to any share in any form whatsoever in the assets or profits of the multi-State co-operative society and shall not have a right to vote;

- (vi) the consequence of default in payment of any sum due by members;
- (vii) the procedure for withdrawal, removal or expulsion of members;
- (viii) the manner in which and the limits upto which the funds of the society may be raised the maximum share capital which any member may hold and the purpose to which the funds may be utilised;
- (ix) the mode of appointment and removal of the directors and other officers of the multi-State co-operative society and the duties and powers of the board;
- (x) the mode of convening and conducting annual and special meetings of the general body and of the board, issue of notices and the business which may be transacted thereat
- (xi) the disposal of net profits;
- (xii) the manner of making, altering and abrogating bye-laws;
- (xiii) the powers, duties and functions of the Chairman or President and his removal on his losing support of the majority;
- (xiv) the powers and duties of the Chief Executive in addition to these mentioned in section 45;

- (xv) the authorisation of an officer or officers to sign documents and to institute and defend suits and other legal proceedings on behalf of the multi-State co-operative society;
- (xvi) the mode of custody and investment of funds;
- (xvii) the mode of keeping the accounts;
- (xviii) the strength of the board;
- (xix) the manner in which penalty may be levied on a member found guilty of breach of the bye-laws;
- (xx) the appointment of a provisional board, wherever necessary;
- (xxi) the manner of sending notices;
- (xxii) the formation or use of reserve fund;
- (xxiii) the purpose for which surplus if any shall be utilised in the event of the winding-up of the multi-State co-operative society;
- (xxix) the conduct of elections to the board and other bodies of a multi-State co-operative society including the number of members to be elected by different constituencies and appointment of retiring officers;
- (xxv) the procedure to be followed in cases of withdrawal, ineligibility and death of members;
- (xxvi) the condition, if any, under which the transfer of share or interest of a member may be permitted;
- (xxvii) the method of appropriating payments made by members from whom moneys are due;
- (xxviii) the constitution and maintenance of various funds to be maintained under the provisions of the Act or rules;
- (xxix) the constitution of a representative general body consisting of delegates or members of the multi-State co-operative society and the method of election of such delegates to exercise the powers of the general body;
- (xxx) the mode of conducting business such as manufacture, purchase, stock-taking and other allied matters;
- (xxxi) in the case of co-operative banks and multi-State thrift and credit societies,—
 - (a) the maximum loan admissible per member;
 - (b) the maximum rate of interest on loans to members;
 - (c) the conditions on which loans may be granted to members;
 - (d) the procedure for grant of loans and advances and for the grant of extension of time and for repayment of such loans, advances, etc.,
 - (e) the circumstances under which a loan may be recalled.

8. Amendment of bye-laws.—(1) The amendment to the bye-laws of a multi-State co-operative society may be made by a resolution passed by a two-third majority of the members present and voting at general meeting of the society.

(2) Now such resolution shall be valid unless notice of the proposed amendment has been given to the members of the multi-State co-operative society in accordance with the bye-laws.

(3) In every case in which a multi-State co-operative society proposes to amend its bye-laws, an application shall be made to the Central Registrar together with :—

- (a) a copy of the resolution referred to in sub-rule (1)
- (b) the particulars indicating the date of the the general meeting at which the amendments were made, the number of days notice given to convene the general meeting, the total number of members on the date of such meeting, the number forming the quorum, the number of members present at the meeting, the number exercising the right of voting and the number voting for the amendment;
- (c) a copy of the relevant bye-laws in force with the amendment proposed to be made together with reasons justifying such amendments;
- (d) four copies of the text of the bye-laws as they would stand after the amendment, signed by the officers duly authorised in this behalf by the board of the multi-State co-operative society;
- (e) a copy of the notice given to the members of the multi-State co-operative society and the proposal to amend the bye-laws;
- (f) a certificate signed by the presiding authority of the general meeting that the procedure specified in sub-rule (1) and sub-rule (2) and in the bye-laws, has been followed; and
- (g) any other particulars that may be required by the Central Registrar in this behalf.

(4) Every such application shall be made within sixty days from the date of the general meeting at which such amendment was passed.

(5) Where the Central Registrar refuses to register an amendment of the bye-laws of a multi-State co-operative society he shall pass an order of refusal together with the reasons therefor and communicate the same by registered post to the Chief Executive of the multi-State co-operative society within seven days from the date of order of refusal.

(6) The procedure outlined above in this rule shall apply to the amendment of the bye-laws of a co-operative society desiring to convert itself into a multi-State co-operative society as per provisions of section 18.

9. Maintenance of registration filed by the society—
(1) Every multi-State co-operative society shall maintain at its registered address a registration file containing :

- (a) the certificate of registration;
- (b) the registered bye-laws;
- (c) all registered amendments to the bye-laws alongwith the certificates of registration of amendments;
- (d) a copy of the Act and the rules.

(2) The registration file shall be kept open for inspection at all times during working hours to the Central Registrar or any other officer authorised by him or any member of the multi-State co-operative society.

10. Change in name of multi-State co-operative society.—(1) The name of a multi-State co-operative society may be changed under section 11 so, however, that it does not refer to any caste or religion denomination and is not inconsistent with the objects of the multi-State co-operative society.

(2) Every change in the name of the multi-State co-operative society shall be made by an amendment of its bye-laws.

(3) After the change in the name is approved by the Central Registrar the multi-State co-operative society shall send the original registration certificate for amendment to the Central Registrar who shall return the same to the multi-State co-operative society duly amended.

CHAPTER III : MEMBERS OF MULTI-STATE CO-OPERATIVE SOCIETIES AND THEIR RIGHTS AND LIABILITIES

11. Conditions to be complied with for admission for membership.—(1) No person shall be admitted as a member of a multi-State co-operative society unless,—

- (a) he has applied in writing in the form, if any, laid down by the multi-State co-operative society or in the form specified by the Central Registrar, if any, for membership;
- (b) his application is approved by the board of the multi-State co-operative society;
- (c) he has purchased the minimum number of shares and paid the value thereof in full or in part in such calls as may be laid down in the bye-laws of the multi-State co-operative society;
- (d) he has fulfilled all other conditions laid down in the Act, the rules and the bye-laws;
- (e) in the case of a multi-State co-operative society or a co-operative society or the national co-operative society or any other corporation owned or controlled by the Government or any Government company or body of persons whether incorporated or not, the application for membership shall be accompanied by a resolution authorising it to apply for such membership

(2) No person shall be eligible for admission as a member of a multi-State co-operative society if he :—

- (a) has not attained the age of 18 years;
- (b) has been adjudged by a competent court to be an insolvent or an undischarged insolvent;
- (c) has been sentenced for any offence, other than offence of a political character or an offence not involving moral turpitude and dishonesty and a period of five years has not elapsed from the date of expiry of the sentence.

(3) Notwithstanding anything contained in these rules or the bye-laws of the multi-State co-operative society, if a member becomes or has already become subject to any disqualifications specified in sub-rule (2), he shall be deemed to have ceased to be a member of the society from the date when the disqualification was incurred.

(4) No individual being a member of a primary level multi-State co-operative society or a multi-State credit society, or a multi-State urban co-operative bank, shall be the member of any other multi-State co-operative society or co-operative society of the same class without the general or special permission of the Central Registrar and where an individual has become a member of two such co-operative societies aforesaid, then either or both of the societies shall be bound to remove him from membership on written requisition from the Central Registrar to that effect.

(5) No multi-State co-operative society shall admit members within thirty days prior to the date of the meeting of its general body.

12. Individual members in the National Co-operative Union of India.—The ex-Presidents of the National Co-operative Union of India Limited, New Delhi who have served their full term of office and other individuals not exceeding 15 in number with the knowledge and experience in the field of co-operation may be admitted as members of the National Co-operative Union of India Limited, New Delhi, provided that :

The ex-Presidents and other individuals admitted as members shall not be eligible to vote or contest in any elections in the National Co-operative Union of India Limited.

13. Refund of shares.—The total refund of share capital of a multi-State co-operative society in any co-operative year shall not exceed 10 per cent of the paid up share capital of the multi-State co-operative society on the last day of the co-operative year immediately preceding.

14. Nomination of heir.—(1) For the purposes of transfer of his share or interest under sub-section (1) of section 27, a member of a multi-State co-operative society may nominate a person to whom in the event of his death, his share or interest shall be transferred. Such member may, from time to time, revoke or vary such nomination.

(2) A nomination made by a member shall not be valid and shall not in the event of death of the member have effect unless, —

- (a) it is made in writing and is signed by the member in the presence of two witnesses attesting the same;
- (b) it is recorded in the books of multi-State co-operative society, kept for the purpose.

15. Procedure of ascertaining the value of share or interest of a member.—Where the member of a multi-State co-operative society ceases to be a member thereof, the sum representing the value of his share or interest in the capital of the multi-State co-operative society to be paid to him or his nominee, or heir or legal representative, as the case may be, shall be ascertained in the following manner, namely :—

- (i) In the case of a multi-State co-operative society with unlimited liability, it shall be the actual amount received by the multi-State co-operative society in respect of such share or interest;
- (ii) In the case of a multi-State co-operative society with limited liability, it shall be the amount arrived at by the valuation based on the financial position of such society as shown in the last audited balance sheet preceding cessation of membership :

Provided that the amount so ascertained shall not exceed the actual amount received by the multi-State co-operative society in respect of such share or interest.

16. Restriction on holding of shares.—No member referred to in clauses (a) and (b) of sub-section (1) of section 19 shall hold more than one-fifth of the share capital of the multi-State co-operative society or have or claim any interest in the shares of the multi-State co-operative society exceeding ten thousand rupees, whichever is less.

17. Shares not to be hypothecated.—The shares of a multi-State co-operative society shall not be hypothecated to that society or any other multi-State co-operative society by the members as a security for a loan.

18. Prohibition on admission of members and transfer of shares on the eve of general meeting.—(1) No multi-State co-operative society shall admit members or approve the transfer of shares within thirty days prior to the date fixed for the general body meeting.

(2) Any person admitted as member and any person in whose favour the transfer of shares have been approved in contravention of this rule shall not have the right to vote at the said general meeting.

19. Disqualification of defaulting member.—A member of a multi-State co-operative society or a representative of defaulting member society shall not be eligible to seek election to any office in, or continue, as a member of the board of such multi-State co-operative society, if he or the society of which he is the representative, commits default in the payment of annual subscription or other sums due to such multi-State co-operative society. A member, or a representative of a defaulting member society, if holding

any office in a multi-State co-operative society, shall forfeit the right to hold such office with effect from the date on which he, or the society of which he is the representative, becomes defaulter as per bye-laws of the multi-State co-operative society or as determined by the board of directors of the multi-State co-operative society.

CHAPTER IV : DIRECTION AND MANAGEMENT OF MULTI-STATE CO-OPERATIVE SOCIETIES

20. Annual General Meeting.—Every multi-State co-operative shall hold the annual general meeting of its members (referred to in section 30) within six months of the close of the co-operative year.

21. Constitution of smaller general body (1) Without prejudice to the provision of sub-section (3) of section 29, a multi-state co-operative society with a membership exceeding one thousand may provide in its bye-laws for the constitution of a smaller general body. The smaller general body so constituted shall exercise such powers as may be specified in the bye-laws of the multi-State co-operative society.

(2) The bye-laws of such society may specify the principle or the basis for constitution of a representative general body and procedures thereto.

22. Interim board and general meeting for first election.—(1) The board of directors selected by the applicants for the registration of the multi-State co-operative society shall hold office till the directors are elected in the first general meeting of the multi-State co-operative society.

(2) The first general meeting for this purpose shall be held within six months of the registration of the multi-state co-operative society.

23. Notice for general meeting.—(1) Annual general meeting of a multi-State co-operative society may be called by giving not less than fourteen days notice in writing.

(2) Special general meeting of a multi-State co-operative society may be called by giving not less than seven days notice in writing.

(3) When a general meeting is called by the Central Registrar under the second proviso to sub section (1) of section 30, he may determine:—

- (i) the period of notice of such meeting which shall not be less than seven days;
- (ii) the time and place of such meeting, and
- (iii) the subjects to be considered in such meeting.

The Central Registrar or any person authorised by him may preside over such meeting.

(4) The notice of general meeting shall be accompanied by a copy each of the audited balance sheet, profit and loss account, together with the auditor's report thereon, relating to the preceding year and the report of the board.

24. Quorum at a general meeting.—(1) Unless otherwise provided in the bye-laws, the quorum for a general meeting shall be one-fifth of the total number of members of the multi-State co-operative society.

(2) No business shall be transacted at any general meeting unless there is a quorum at the time when the business of the meeting is due to commence.

(3) If within half-an hour from the time appointed for the meeting a quorum is not present, the meeting shall stand adjourned :

Provided that a meeting which has been called on requisition of the members shall not be adjourned but dissolved.

(4) If at any time during the meeting sufficient number of members are not present to form the quorum, the Chairman or the member presiding over the meeting on his own, or on his attention being drawn to this fact, shall adjourn the meeting and the business that remains to be transacted at this meeting, if any, shall be disposed of in the usual manner at the adjourned meeting.

(5) where a meeting is adjourned under sub-rule (3) or sub-rule (4), the adjourned meeting shall be held either on the same day or on such date, time and place as may be decided by the Chairman or the member presiding over the meeting.

(6) No business shall be transacted at any adjourned meeting other than the business on the agenda of the adjourned meeting.

(7) No quorum shall be necessary in respect of an adjourned general meeting.

25. Voting in general meeting.—(1) All resolutions which are put to vote at the general meeting shall be decided by a majority of the members present and voting unless otherwise required under Act, these rules or the bye-laws of the multi-State co-operative society. Voting shall be by show of hands unless a poll is demanded by at least ten members present at the meeting. If no poll is demanded, a declaration by the Chairman/President of such meeting that a resolution has been carried or lost and an entry to that effect in the minutes of the proceedings shall be conclusive proof of the fact that such resolution has been duly carried or lost.

(2) If a poll is demanded, the votes shall be taken by ballot as may be decided by the Chairman of the meeting unless otherwise specified in the bye-laws in this behalf, and the result of the poll shall be deemed to be the decision of the general meeting regarding the resolution over which the poll is demanded.

(3) When a poll is taken, the number of members voting for or against a resolution shall be recorded in the minutes of the proceedings.

(4) In the case of equality of votes whether on a show of hands or on a poll, the Chairman of the meeting at which show of hands takes place or the poll is taken, shall have a second or casting vote.

26. Minutes of the general meeting.—Minutes of the proceedings of the general meeting shall be entered in a minutes book kept for the purpose and

shall be signed by the Chairman of the meeting. The minutes so signed, shall be an evidence of the correct proceedings of that meeting.

27. Procedure for conduct of elections.—(1) Notwithstanding anything contained in these rules, and without prejudice to the generality of the powers of the Central Government under sub-section (1) of section 35, the election of the members of the board of directors of the national co-operative society specified in the Second Schedule to the Act and such other multi-State co-operative society or class of multi-State co-operative societies as the Central Government may, by general or special order, notify, shall be conducted by such returning officer or officers as may be appointed by the Central Registrar in this behalf. The election in such societies shall be conducted in the manner specified in Schedule.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) where a requisition to appoint a returning officer to conduct an election is received from not less than 1/5 of the total number of members eligible to vote in a multi-State co-operative society sixty days in advance of the date for election, the Central Registrar shall appoint a returning officer to conduct election in the manner specified in the Schedule.

28. Election of office-bearers.—As soon as the members of the board have been elected, the returning officer referred to in sub-rule (1) of rule 27, or the person presiding over the general meeting, as the case may be, shall, notwithstanding anything contained in the bye-laws of the multi-State co-operative society specifying the period of notice, convene a meeting of the newly elected members of the board for the purpose of election of the President|Chairman, Vice-President|Vice-Chairman or other elected office-bearers of the society, by whatever name they are called. Such a meeting of the board shall not be conducted unless a majority of the number of members of the newly constituted board, as per bye-laws, are present.

29. Custody of record of elections conducted.—After declaration of the result of election, the returning officer, (referred to under sub-rule (1) of rule 27) or the Chairman of the meeting, as the case may be, shall handover the ballot papers and records, if any, relating to the election of the members of the board of directors and the office-bearers to the Chief Executive of the multi-State co-operative society in sealed cover. They shall be preserved by the Chief Executive of the society for a period of six months from the date of election or till such time a dispute or an appeal thereof regarding elections, if any, is disposed of, whichever is later, and shall thereafter be destroyed.

30. Restrictions and conditions for payment of honorarium to the Chairman and the President.—A multi-State co-operative society may provide in its bye-laws for the payment of honorarium to the elected Chairman or President of the board of directors, out of profits, in respect of specific services rendered by him, on such scale as may be laid-down in the bye-laws of such a society, but in no case exceeding the

limit and terms and conditions hereunder referred to :

- (a) that the society's financial position is sound;
- (b) that for its recurring expenses it does not depend on grants or subsidies from the Central Government or the State Government; and
- (c) that the honorarium to be paid, whether as a consolidated amount or in the shape of daily allowance in respect of the days of halt at the headquarters, in addition to the sitting fees in respect of board meetings as and when such meetings are held, is limited to rupees twenty-five thousands per year.

31. Central Government or State Government nominees on the board.—(1) Where the Central Government or the State Government has subscribed to the share capital of a multi-State co-operative society, or has guaranteed the repayment of principal and payment of interest on debentures issued by such society, or has guaranteed the repayment of principal and payment of interest on loans and advances to such society, or has provided grant or subsidy to such society, the Central Government or the State Government, as the case may be, or any other person authorised by the Central Government or the State Government, shall have the right to nominate on the board such number of persons not exceeding 3 or 1/3rd of the total number of members thereof, whichever is less.

(2) Notwithstanding anything contained in these rules, the bye-laws of a multi-State co-operative society may provide for the nomination by the Central or State Government of persons in excess of the limits referred to in sub-rule (1).

32. Additional measures and acts to be undertaken by the board.—The board may take any of the measures or do any of the acts mentioned below as may be necessary or expedient for the purposes of carrying out its functions under the Act and the rules made thereunder :

- (i) placing before the general body the annual report and the audit report;
- (ii) recommending the distribution of profits to the general body;
- (iii) taking decisions on matters relating to withdrawals, transfer, retirement, refund or forfeiture of shares;
- (iv) purchasing, selling, or otherwise acquiring or disposing of moveable property of such value as may be specified in the bye-laws;
- (v) laying down criteria for determining defaults by members;
- (vi) determining the terms and conditions of collaboration with other co-operative societies and others;
- (vii) sanctioning of contracts of any values, unless otherwise specified in the bye-laws of a multi-State co-operative society;

(viii) appointment of trustee or trustees, attorney or attorneys, agent or agents for the business of the multi-State co-operative society;

(ix) acceptance or rejection of resignation from the members of the board.

33. Meeting of the board.—(i) The board shall meet at least once in every quarter, provided that the total number of the meetings of the board shall not ordinarily exceed six in a year.

Provided further that this provision will not apply to multi-state thrift and credit societies.

(ii) The meeting of the board of the multi-State co-operative society shall ordinarily be held at the registered office of such society.

34. Committees of the board.—(i) The board of a multi-State co-operative society may constitute an Executive Committee and other committees or sub-committees as may be considered necessary.

(ii) Besides the Executive Committee, the number of other committees or sub-committees referred to in sub-section (1) of section 46 shall not exceed two:

Provided that the board may with the approval of the Central Registrar constitute more than two Committees.

35. Constitution of National Co-operative Societies Selection Committee.—(1) The Central Government shall constitute a body to be called the National Co-operative Societies Selection Committee (hereinafter referred to as the Selection Committee) consisting of the following persons :

- | | |
|--|-----------------------|
| (i) The Secretary to the Government of India
Department of Agriculture and Cooperation | Chairman; |
| (ii) The Additional Secretary to the Government of India
Department of Agriculture and Cooperation dealing with cooperation | Member; |
| (iii) Chairman of two national co-operative societies to be nominated by the Central Government | Member; |
| (iv) One expert in the management to be nominated by the Central Government | Member; |
| (v) The Managing Director, National Co-operative Development Corporation | Member; |
| (vi) Central Registrar of Co-operative Societies | Member/
Secretary. |

(2) The Selection Committee shall prepare a list of persons eligible for appointment to the post of the Chief Executive and other managerial posts in

the national co-operative societies, the maximum pay-scale of which exceeds rupees four thousand per month in the manner hereinafter provided.

(3) The Central Registrar shall, on the requisition received from the national co-operative society, convene the meeting of the Selection Committee for the purpose of preparation of list for the appointments to the post or posts for which the requisition has been received.

(4) The Selection Committee shall,—

- take appropriate steps to advertise, circulate or otherwise call for the names for the posts referred to in sub-rule (2);
- screen the names received and prepare list of persons, after interview if necessary, suitable for appointment for the said posts in order of merit and forward it to the Central Government for its onward transmission to the concerned national co-operative society;

Provided that in the case of the existing Chief Executive or persons employed in other managerial posts in the national co-operative society on the date of the coming into force of these rules, who are in regular employment of the society, no such reference to the Selection Committee will be necessary.

Provided further that in the case of the Chief Executives or persons employed in other managerial posts who are on deputation with the national co-operative society on the date of the enforcement of these rules, a reference to the Selection Committee shall be necessary on the expiry of the terms of deputation of such Chief Executives or persons.

(5) The national co-operative society shall appoint the persons to the post of the Chief Executive and other managerial posts mentioned in sub-rule (2) from the list of persons recommended by the Selection Committee.

(6) The Selection Committee may co-opt two experts at the time of selection of persons according to the requirements of posts or category of posts for which the list of persons is to be prepared.

CHAPTER—V

SETTLEMENT OF DISPUTES

36. Procedure in proceedings before Central Registrar.—(1) A reference to the Central Registrar of any dispute under section 74 shall be in writing. Every such reference shall be accompanied with a fee of rupees ten for the money claims not exceeding rupees one thousand and rupees fifty in all other cases.

(2) On receipt of a reference under sub-rule (1) the Central Registrar may elect to decide the dispute himself or refer it for disposal to any other person who has been invested with powers of the Central Registrar under section 76 by the Central Government.

(3) The Central Registrar or other person deciding the dispute shall record a brief note of the evidence of the parties and witnesses who appear before him and upon the evidence so recorded and after consideration of any documentary evidence produced by the parties, a decision shall be given in accordance with justice, equity and good conscience by the Central Registrar or other person deciding the dispute. The decision given shall be in writing.

In the absence of any party duly summoned to attend, the dispute may be decided ex-parte. Ex-parte decision may, on sufficient cause for non-attendance being shown, be set aside by the Central Registrar or other person deciding the dispute, and the dispute ordered to be re-taken on the register of disputes and disposed of :

Provided that no application for setting aside an ex-parte decision shall lie unless made within thirty days from the date of such decision and the party for whose non-attendance such decision was made had been duly served with the notice, or in other cases within thirty days from the date of knowledge of such decision having been made.

(4) The decision shall be communicated to the parties by,—

(i) Pronouncement of the decision ;
or

(ii) registered post to any party which may be absent on the date the decision is given.

(5) The Central Registrar or the person deciding the dispute, shall have power to appoint or remove a guardian for the party to the dispute, if any such party is a minor or a person with unsound mind or mental infirmity, and is incapable of protecting his interests.

(6) A duly certified copy of the decision shall, on application, be given to the parties to the dispute by the Central Registrar or the person deciding the dispute, on payment of copying charges at the rate of rupee one per page.

CHAPTER—VI

APPEALS AND REVISIONS

37. Appeals against order of Central Registrar.—For the purpose of clause (a) of sub-section (2) of section 90 of the Act, an appeal against any decision or order shall be made if the decision or order was made by —

(a) the Central Registrar appointed under sub-section (1) of Section 4 of the Act, to the Secretary to the Government of India in the Department of Agriculture and Cooperation,

(b) any officer of the Central Government or any officer of the State Government of the rank of Registrar on whom powers of the Central Registrar have been conferred under sub-section (2) of Section 4 of the Act, to the Additional Secretary to the

Government of India in the Department of Agriculture and Cooperation.

(c) any other officer of the State Government on whom powers of Central Registrar have been conferred under sub-section (2) of section 4 of the Act, to the Chief Director (Cooperation) in the Ministry of Agriculture and Co-operation.

38. Procedure regarding appeals and application for revision.

(1) An appeal under sub-section (2) of section 90 or an application for revision under section 92 shall be either presented in person or sent by registered post to the appellate or revising authority.

(2) The appeal or the application for revision shall be in the form of a memorandum and shall be accompanied by the original or certified copy of the order appealed from or sought to be revised.

(3) Every appeal or application for revision shall :—

(a) specify the name and address of the appellant or applicant and also the name and address of the respondent, as the case may be ;

(b) state by whom the order appealed from or sought to be revised was made ;

(c) set forth concisely and under distinct heads, the grounds of objection to the order appealed from or sought to be revised together with a memorandum of evidence ;

(d) State precisely the relief which the appellant or the applicant claims ; and

(e) give the date of order appealed from or sought to be revised.

(4) Where,—

(a) an appeal under sub-section (2) of section 90 is preferred after the expiry of sixty days specified in the said sub-section, or

(b) an application for revision under sub-section (1) of section 92 is made after the expiry of ninety days from the date on which the decision or order to which the application relates is communicated to the applicant,

it shall be accompanied by a petition supported by an affidavit setting forth the facts on which the appellant or the applicant relies to satisfy the appellate or revising authority that he had sufficient cause for not preferring the appeal or the application for revision within the period mentioned in clauses (a) and (b),

(5) On receipt of the appeal or the application for revision, the appellate or revising authority shall as soon as possible examine it and ensure that :—

- (a) the person presenting the appeal or the application has the locus standi to do so;
- (b) it is made within the prescribed time limit, and
- (c) it conforms to all the provisions of the Act and these Rules.

(6) The appellate or revising authority may call upon the appellant or the application for revision to remedy the defects, if any, or furnish such additional information as may be necessary, within a period of fifteen days of the receipt of the notice to do so. If the appellant or the applicant for revision fails to remedy the defects or furnish the additional information called for within the said period, the appeal or the revision petition may be dismissed.

(7) The appellate or revising authority may, before passing orders under section 90 or under section 92 obtain from any subordinate officer such further information in regard to the enquiry or the proceedings for the purpose of verifying the regularity of such proceedings or the correctness, legality or propriety of any decision passed or order made therein. The appellate or revising authority may also call for and obtain from the parties connected with such enquiry or proceedings such information as is necessary with reference to the examination of the records of enquiry or proceedings and the information obtained from the subordinate officer.

(8) The appellate or revising authority shall on the basis of the enquiry conducted and with reference

to the records examined, pass such order on the appeal or on the application for revision as may seem just and reasonable.

(9) Every order of the appellate or revising authority under sub-section (2) of section 90 or 92 shall be in writing and it shall be communicated to the appellant or applicant and to such other parties as in the opinion of that authority are likely to be affected by the decision or order and to the officer concerned against whose order the appeal of the application for revision was made.

39. Application for Review.—(1) Every application under section 93 shall be in the form of a memorandum setting forth concisely and under distinct heads the new and important facts which after the exercise of due diligence, were not then within the knowledge of the applicant or could not be produced by him when the order was made or mistake or errors apparent on the face of the record or other reasons on the basis of which review is sought. It shall be accompanied by a memorandum of evidence.

(2) The application shall be accompanied by the original or a certified copy of the order to which the application relates.

(3) No application for review shall be entertained unless it is accompanied by such additional number of copies as there are parties to the original order.

(4) The application shall, so far as it may be necessary, be disposed of by the appellate authority in such manner as may be deemed fit, provided that no order prejudicial to any person shall be passed unless such person has been given an opportunity of making his representation.

FORM I

[See sub-rule (1) of rule 3]

Application for registration of a multi-State co-operative society under the Multi-State Cooperative Societies Act, 1984

To,

The Central Registrar of
Co-operative Societies.

Sir,

We submit herewith a proposal for registration of the following multi-State co-operative society alongwith enclosures as indicated below :

2. We also declare that the information given herewith including that in the enclosures is correct to the best of our knowledge :

- (a) Name of the proposed multi-State co-operative society;
- (b) Headquarters and address to be registered;
- (c) Area of operations;
- (d) Main objectives;

- (h) Name and address of the applicant for the purpose of further correspondence _____

5. The particulars of the applicants are given hereunder :

Address	Amount subscribed to share capital	In the case of representative of Society or a multi-State cooperative society, whether he is Chairman/President or Chief Executive of that Society	Signature
6	7	8	9

†Blanks to be filled in.

FORM II

[See sub-rule (1) of rule 4]

Register of applications for registration of multi-State Co-operative Societies received by the Central Registrar

Sl. No.	Name of the proposed multi-State co-operative society and the Chief Promoter	Complete address	Date of receipt and how received	Date and reference number of acknowledgement
1	2	3	4	5

No. and date on which additional information is called	Prescribed date by which information is called	Date on which additional information received
6	7	8

No. and date of the report, if any sent to the Central Government, if the society is not registered within 6 months	No. and date of order of	Initial	Remarks
9	Registration	Refusal	
	10	11	12
			13

SCHEDULE

1. Procedure regarding conduct of elections to the board of multi-State co-operative societies—Notwithstanding anything contained in the rules, and without prejudice to the generality of the powers of the Central Government in sub-section (1) of the section 35, the election of the members of the board of directors of national co-operative societies specified in the Second Schedule to the Act and such other multi-State co-operative societies or class of multi-State co-operative societies, as the Central Government may, by general or special order notify, shall be conducted by such returning officers as may be appointed by the Central Registrar in this behalf. The election in such societies, shall be conducted in the manner hereinafter provided :

2. Election Programme.—(a) The board of directors in office shall meet sixty clear days in advance of the date of expiration of its term and by resolution determine the date, time and place for convening

a general body meeting for the conduct of elections of its successor board. This provision will apply mutatis mutandis to such multi-State co-operative societies as are under the charge of the administrator appointed under sub-section (1) of section 48.

(b) A copy of the decision referred to in subparagraph (a) shall forthwith be sent to the Central Registrar.

(c) On receipt of the decision referred to in subparagraph (b), the Central Registrar shall appoint a returning officer under sub-section (1) of section 35. The returning officer shall, shortly thereafter, send intimation by local delivery or by registered post about the day, time and place of the general meeting to each of the members of the multi-State co-operative society. Where other co-operative societies or multi-State co-operative societies are members, the returning officer shall call on such societies to send the name of their Chairman

or President or the Chief Executive as a representative (hereinafter referred to as the delegate) in accordance with the provisions contained in sub-section (3) of section 29 together with the resolution of the board of the society and the specimen signature of the Chairman, President or the Chief Executive duly attested and bearing the seal of the society so as to reach him at least 21 clear days prior to the date fixed for the general meeting. Where there is no board of such co-operative society or other multi-State co-operative society, the administrator, by whatever name called, of such co-operative society or other multi-State co-operative society shall intimate the returning officer in writing under his signature at least 21 clear days prior to the date fixed for the general meeting that he shall represent such society in the general meeting. Where no such resolution or communication intimating the name of delegate is received by the date fixed or where any intimation changing the name of the delegate is received after such date, it shall not be accepted for inclusion in the list of members|delegates of member-societies. Fresh resolutions shall be required for every general meeting at which election shall be held.

(d) It shall be the duty of the board of directors in office, or the administrator, as the case may be, to bring up-to-date the register of members and such other registers, as the returning officer may require and handover such records, register or registers to the returning officer thirty days prior to the date fixed for the general meeting for the purpose of election.

(e) The election shall be held at a general meeting of the society convened for the purpose, of which not less than fourteen days notice shall be given to the members. Such elections shall take place after all other matters included in the agenda have been considered. For the conduct of elections, the returning officer shall preside over the meeting.

(f) The notice of the general meeting shall be sent to the members by any of the following modes, namely :—

- (i) by local delivery; or
- (ii) by registered post

(g) Notice of the general meeting shall also be affixed on the notice board of the multi-State co-operative society and its branches, if any. The notice shall contain information regarding :—

- (i) the number of vacancies to be filled by election;
- (ii) the area of the constituency (specified in the bye-laws) from which the members are to be elected;
- (iii) the qualifications, if any, specified in the bye-laws for eligibility for membership on the board;
- (iv) the name of the returning officer, date, place and the hours between which nomination paper shall be filed by the members, such date being not less than one clear day before the date fixed for election or

if that happens to be a holiday the day preceding which is not a public holiday.

Explanation:—For the purpose of this sub-paragraph the term “public holiday” means any day which is declared as a public holiday under section 25 of the Negotiable Instruments Act, 1881 (26 of 1881) or any day which has been notified by the Central Government, or as the case may be, the State Government to be a public holiday for the offices of the Central Government or the State Government.

- (v) the date on which and the time and place at which the nomination papers will be taken up for scrutiny;
- (vi) the date and time of withdrawal; and
- (vii) the date on which, the place at which and the hours between which polling will take place.

3. Preparation of list of members|delegates.—(a) the multi-State co-operative society shall prepare a list of members eligible to vote as it stood on the date, thirty days prior to the date fixed for the poll and publish copies of the list by affixing them on the notice board at the head office of the society and all its branches, if any, not less than fifteen days prior to the date fixed for election. The list shall specify :—

- (i) the admission number and name of the member, the name of the father or husband, and the address of such member in the case of an individual member; and
- (ii) the admission number, the name of the society, name of the delegate proposed to represent the society, in the case of a member society.

(b) A copy of the list shall be supplied by the society to any member on payment of such fee as may be specified by the board. Where no fees has been specified, the person authorised as per bye-laws of the society shall supply such list on payment of an amount of rupees five.

4. Nomination of candidate.—(a) Nomination of the candidate for election shall be made in the Nomination Form attached to this Schedule which on application shall be supplied by the returning officer or any other officer authorised by him in this behalf, to any member free of cost.

(b) Every nomination paper shall be signed by two members whose names are included in the list of the members|delegates. One of the members shall sign the form as proposer and the other as seconder for the nomination. The nomination paper shall also contain a declaration signed by the candidate, expressing his willingness to stand for election.

(c) Every nomination paper shall be presented in person or sent by registered post, as acknowledgement due, by the candidate himself or his proposer or seconder to the returning officer or any person authorised by him in this behalf, so as to reach him before the date and hour specified in the notice of

meeting as per paragraph 2(g). The returning officer or any officer authorised by him who receives the nomination paper shall enter on the nomination paper its serial number and certify the date and hour at which the nomination paper is received by him and shall immediately give a written acknowledgement for the receipt of the nomination papers if presented in person, which shall also bear the seal of the society. The returning officer shall, at the close of the time fixed for the receipt of nomination papers, prepare and display on the notice board of the society, a list of nominations received by him. Any nomination paper which is not delivered or received on or before the date and time fixed for its receipt, shall be rejected.

(d) No person shall be nominated as a candidate for election to fill a seat on the board if he :

- (i) is ineligible to vote.
- (ii) is disqualified to be the member|delegate under the provisions of the Act or a member of the board under these rules ; and
- (iii) does not possess the necessary qualifications specified in the bye-laws of the society for election as member of the board.

5. Scrutiny of Nomination Papers.—(a) (i) On the day fixed for the receipt of nomination papers, the returning officer shall, at the appointed hour, take up the scrutiny of nomination papers. The candidate or the proposer or seconder of each of the candidate may be present at the time and place when nomination papers are scrutinised.

(ii) The returning officer shall examine the nomination papers and shall decide all objections which may be made by any candidate or his proposer or seconder in respect of any nomination and may, either on such objection, or on his own motion and after such summary enquiry, if any, as he thinks necessary, reject any nomination.

Provided that the nomination of a candidate shall not be rejected merely on the ground of an incorrect description of his name or the name of his proposer or seconder or of any other particulars relating to the candidate or his proposer or seconder, as entered in the list of members referred to in paragraph 3 (a), if the identity of the candidate, proposer or seconder, as the case may be, is established beyond reasonable doubt.

(iii) The returning officer shall endorse on each nomination paper his decision accepting or rejecting the same as the case may be, and if the nomination paper is rejected, he shall record in writing a brief statement of his reasons for such rejection.

(iv) The returning officer shall not allow any adjournment of the proceedings except when proceedings are interrupted or obstructed by riot or affray or by causes beyond his control.

(v) The list of valid nominations as decided by the returning officer shall be published on the notice board of the society containing the names in the alphabetical order in English and address of the candidate as given in the nomination paper on the same day on which the scrutiny of the nomination paper is completed.

(b) Any candidate may withdraw his candidature by notice in writing signed by him and delivered in person or by his proposer or seconder at any time after the presentation of the nomination papers but before the date and time specified in paragraph 2(g) (vi) for such withdrawal. A notice of withdrawal of candidate once given shall be irrevocable.

6. Voting.—(a) If for any area or constituency for which election is to be held, the number of candidates whose nomination papers have been declared valid, does not exceed the number of candidates to be elected for that area or constituency, the returning officer shall at the general meeting convened for the purpose of the election, declare them to have been duly elected to the board. If the number of candidates whose nominations are valid exceeds the number to be elected for any area or constituency, the returning officer shall arrange for conducting a poll on the date and time fixed for the purpose. The returning officer may appoint as many polling officers as may be necessary for conducting the poll.

(b) A candidate contesting the election may, by a letter to the returning officer, appoint an agent to represent him where polling is held, to identify the voters and to watch the recording of votes. Such letter shall contain the consent in writing of the agent concerned.

(c) Canvassing of votes by any person at the place where elections are to be conducted shall be prohibited.

(d) Immediately before the commencement of the poll, the returning officer shall show the empty ballot box to such persons as may be present at the time and shall then lock it up and affix his seal in such manner as to prevent its being opened without breaking the seal. The candidate or his agent may also affix his own seal, if he so desires.

(e) Every member|delegate who desires to exercise his right of vote shall be supplied with a ballot paper containing the names of contesting candidates arranged in alphabetical order either printed, type-written or cyclostyled, according to convenience, on the ballot paper. The ballot paper shall also bear the seal of the society and also the initials of the returning officer and further contain a column, for the voter to inscribe a mark 'X' against the name or names of the persons to whom he wants to vote.

(f) Each polling station and where there is more than one polling booth at a station, each such booth shall contain a separate compartment in which the members|delegates can record their votes in secrecy.

(g) Every member who desires to exercise his votes shall enter the polling station with an identity card, if any, given to him. The polling officer shall identify the member by putting questions to him with reference to the list of members|delegates eligible to vote in the polling station, furnished to him. If the polling officer is satisfied about the identity of the member and if there is no objection from any candidate or his polling agent present at the

polling station, he shall issue a ballot paper to him. On receipt of such ballot paper, the member shall proceed to the polling compartment set apart for the purpose and indicate the person or persons in whose favour he exercises his vote by inscribing a mark 'X' against the name of the candidate or candidates, as the case may be, and put the ballot paper in the ballot box kept for the purpose with utmost secrecy. If owing to blindness or other physical infirmity or illiteracy a member is unable to inscribe the mark on the ballot paper the polling officer, and where no such polling officer is appointed, the returning officer shall ascertain from him the candidate or candidates, in whose favour he desires to vote, inscribe the mark 'X' on his behalf and put the ballot paper in the ballot box.

(h) (i) Every member whose name is entered in the list of members/delegates eligible to vote, furnished to the polling officer, is entitled to poll his vote, unless there is a challenge by the candidate or his agent against his identity. If there is such a challenge about the identity of a member or if the polling officer feels any reasonable doubt, he shall then refer the matter to the returning officer who shall make a summary enquiry and decide the question with reference to the books of the society.

(ii) The returning officer shall not entertain any challenge by a candidate or his polling agent, of a member's identity until the person who challenges pays a fee of Rs. 5/- (Rupees five only) for every such vote, in cash. The returning officer shall thereafter entertain the challenge and ask the member who has come to poll the vote to affix his thumb-impression or signature, as the case may be, on a declaration describing his identity. If he refuses to do so, the member shall not be allowed to vote. If, on the other hand, as a result of such summary enquiry the identity of the member is established to the satisfaction of the returning officer, the polling officer shall issue ballot paper, and the member shall then be allowed to vote. In such cases the challenge fees paid shall be forfeited. At the end of the poll, the returning officer, shall render an account of challenge fees collected, fees refunded to the persons who challenged and the fees forfeited to the society together with a brief note on the decision arrived at by him after the summary enquiry in each case.

(i) (A) If at any stage of the polling, the proceedings are interrupted or obstructed by any riot or affray or if at such election it is not possible to take poll for any sufficient cause, the returning officer shall have power to stop the polling after recording his reasons for such an action.

(B) Where the poll is stopped under clause (A) or where counting of votes is rendered impossible on account of destruction or loss of ballot boxes or any other sufficient reason, the returning officer shall stop the polling recording the reasons for such action in the minute book of the society.

(j) No voter shall be admitted after the hour fixed for the polling; but a voter who enters the premises where ballot papers are being issued before

the close of the polling hour shall be issued the ballot paper and allowed to vote.

(k) The counting of votes shall take place immediately after close of the poll. If this is not possible for reasons beyond the control of the returning officer, the ballot box shall be sealed with the seal of the returning officer and of the contesting candidates or of their agents, if they so desire, and deposited with the society for safe custody. The returning officer shall then announce and also intimate in writing to the candidates or their agents present the time and place at which the counting shall commence next day. Votes shall be counted by or under the supervision of the returning officer. Each candidate and his authorised agent shall have a right to be present at the time of counting. But the absence of any candidate or his agent at the time of counting shall not vitiate counting or announcement of results by the returning officer.

7. General (a) A ballot paper shall be rejected by the returning officer, if :

- (i) it bears any mark or writing by which the member who voted can be identified; or
- (ii) it does not bear the seal of the society or the initial of the returning officer; or
- (iii) the mark indicating the vote thereon is placed in such manner as to make it doubtful to which candidate the vote has been cast ; or
- (iv) is so damaged or mutilated that its identity as a genuine ballot paper cannot be established.

(b) If after the counting of the votes is completed, an equality of votes is found to exist between any candidates and the addition of one vote will entail any of those candidates to be declared elected, the returning officer shall forthwith decide between these candidates by lot and proceed as if the candidate on whom the lot falls had received an additional vote and declare him elected.

(c) After the returning officer has completed the counting of votes, he shall prepare a return of the results of the polling and shall forthwith declare the results. The returning officer, shall immediately thereafter record the proceedings of the election in a comprehensive report which shall form part of the records of the society and shall be binding on all. A copy of such a report together with a copy of the return of the results of polling, shall be submitted by the returning officer to the Central Registrar.

8. Mode of election of members of the board of Multi-State co-operative societies other than those referred in Paragraph (1) The election of the members of the board of a multi-State co-operative society not falling under paragraph 1 shall be by show of hands.

(2) The election shall be held at a general meeting of the multi-State co-operative society convened for the purpose, of which not less than 14 clear days notice shall be given to the members. The notice of the general meeting shall be sent to the members by

any of the modes specified in sub-paragraph (f) of paragraph 2 and shall contain information regarding :—

- (a) the number of vacancies to be filled by election;
- (b) the area or the constituency, if any, from which members of the board are to be elected ; and
- (c) the date on which, the place and the hours at which elections will take place.

(3) The board of directors or the administrator or administrators appointed under sub-section (1) of section 48, as the case may be, shall prepare a list of individual members and delegates of member-societies as it stood on the date, 30 days prior to date on which elections are to take place and affix a copy thereof to the notice board of the society not less than 15 days prior to the date fixed for the election. A copy of the said list shall be supplied by the society to any member on payment of such fees as may be specified by the board, or the administrator, as the case may be. Where no fees has been specified, the President|Chairman of the society, or the administrator shall supply such list on payment of Rs. 2/-

(4) Notwithstanding anything contained in this Schedule, the President|Chairman or the Vice-President|Vice-Chairman if they are not candidates seeking election to the board, shall preside over the meeting. In case they are seeking election to the board, the general body shall elect a member who is not a candidate seeking election to the board, as the Chairman of the meeting for the conduct of elections.

Provided that in respect of a society falling under this rule for which an administrator has been appointed under sub-section (1) of section 48, the administrator shall be the Chairman of the meeting.

(5) The nomination of the candidates for election shall be made at the meeting. The Chairman of the meeting shall decide the objections, if any, which may be made at the time to any nomination after making such summary enquiry as he thinks necessary and announce the names of candidates as per valid nominations.

(6) If for any area or constituency for which election is to be held the number of candidates in respect of whom valid nominations have been announced does not exceed the number of candidates to be elected for that area or constituency, the candidates for whom valid nominations have been announced shall be deemed to have been elected for that area or constituency, as the case may be, and the Chairman of the meeting shall make a declaration to that effect. If the number of candidates in respect of whom valid nominations have been announced for any area or constituency exceeds the number of candidates to be elected, a poll shall be taken and the Chairman shall then read out the names of the contesting candidates. He shall thereafter record the number of votes polled, for and against each such candidate, ascertained either by show of hands or

by ballot, as the case may be, and record the same in the minute book of the society. The Chairman shall announce the number of votes polled by each candidate and the result of the elections which shall also be recorded in the minutes book of the society and attested by him.

(7) Where secret ballot is demanded by the members of the general body, a formal resolution to this effect will be put to vote and adopted. The meeting shall adjourn for a brief period to enable the Chairman to make arrangements for the secret ballot.

(8) After counting, the general body shall again assemble where the results of the poll shall be announced as in clause (6) of paragraph 8.

(9) Elections of the boards of societies which has to be conducted by returning officer on requisition from the members: Notwithstanding anything in sub-paragraph (1) of paragraph 8, where a requisition to appoint a returning officer to conduct an election is received from not less than one-fifth of the total number of members on the rolls and eligible to vote in a multi-State co-operative society, sixty days in advance, the Central Registrar, shall appoint a returning officer to conduct election in the manner specified in paragraphs 2 to 7.

10. Election of office-bearers : (1) As soon as the members of the board have been elected, the returning officer referred to in paragraph 1, 2 and 9, or the President|Chairman referred to in paragraph 8 shall, notwithstanding anything in the bye-laws of the multi-State co-operative society specifying the period of notice, convene a meeting of the newly constituted board for the purpose of election of the President|Chairman, Vice-President|Vice-Chairman or other elected office bearers of the society, by whatever name they are called. Such a meeting of the board shall not be conducted unless a majority of the number of members newly constituted board, as per bye-laws, are present.

(2) At the meeting so convened by the President|Chairman referred to in paragraph 8 (under sub-paragraph (1)) the members of the newly constituted board of multi-State co-operative societies shall from among themselves, elect a member who is not a candidate seeking election to any office, as the Chairman of the meeting for conducting the elections. The election of office-bearers of such multi-State co-operative societies shall be by show of hands unless a poll is demanded in which case, it shall be held by secret ballot.

(3) The election of office-bearers of the societies referred to in paragraph 1 and 9 shall be conducted by the returning officer appointed by the Central Registrar. The nomination of the candidates for election in such cases shall be made at a meeting of the newly constituted board of directors. The returning officer shall decide the objections, if any, which may be made at the time, to any nomination and after making such summary inquiry, as he thinks necessary, announce the name of valid nominations.

(4) If for any office for which elections are to be held, the number of candidates in respect of whom

valid nomination have been announced, does not exceed the number of candidates to be elected for that office, the candidates for whom valid nomination have been announced shall be deemed to have been elected for that office and the returning officer shall make a declaration to that effect. If the number of candidates in respect of whom valid nominations have been announced for any office exceeds the number of candidates to be elected, a poll shall be taken by the returning officer. The returning officer shall, thereafter, announce the number of votes secured by each candidate and the result of election which also be recorded by him.

11. Custody of record of elections conducted : After declaration of the result of election, the returning officer referred to under paragraph 1, 9 and 10 of the Chairman of the meeting under paragraph 8, as the case may be, shall handover the ballot papers and records, if any, relating to the election of the members of the board of directors and the office-bearers to the chief executive of the multi-State co-operative society in sealed covers. They shall safely be preserved by the chief executive of the society for a period of six months from the date of election or till such time a dispute or an appeal thereof regarding elections, if any, filed is disposed of, whichever is later, and shall thereafter be destroyed.

NOMINATION FORM

[See paragraph 4 (a)]

1. Name of the multi-State :
co-operative society &
address
2. Name of the candidate in :
case of an individual
member/name of the dele-
gate and the member
co-operative society
multi-State co-operative
society which he is
representing.
3. Serial No. :
in the register of
members.
4. Father's or husband's :
name (in case of an
individual member)
5. Address :

6. Name of the proposer in :
case the proposer is an
individual member and the
name of the society and the
delegate in the case proposer
is a delegate of a society.
7. Serial No. :
of the proposer in the
register of members.
8. Signature of the proposer :
9. Name of the seconder when :
the seconder is an indivi-
dual member and name of
the society and the dele-
gate in case the seconder
is a delegate of a
society.
10. Serial No. :
of the seconder in
the register of
members.
11. Signature of the :
seconder.

CANDIDATE'S DECLARATION

I declare that I am willing to stand for election and that, to the best of my knowledge and belief I have not incurred any disqualification for membership of the board of multi-State co-operative society in terms of the Act, the rules and the bye-laws of the multi-state co-operative society.

(Signature of the candidate)

Endorsement by the Returning Officer

This nomination paper was presented to me in personal.....received by registered post onat.....hrs.

Place :

Date :

Signature of Returning Officer
or person authorised by him.

[No. L-11012/1/85-L&M]

K. N. ARDHANARESWARAN, Add. Secy.